वर्ष 13 • अंक 28 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 20 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

आलू-प्याज की मांग बढ़ी, कीमतों में तेजी

अजय त्यागी ▶▶ पृष्ठ 2

वित्तीय नतीजों के लिए कंपनियों को मोहलत

डॉलर रु. 75.00 ▲ 80 पैसे | यूरो रु. 80.60 ▼ 90 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40334 ▼ 41 रुपये | सेंसेक्स 28288.20 ▼ 581.30 | निफ्टी 8263.50 ▼ 205.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 8205.90 ▼ 57.50 | ब्रेंट क्रूड 24.10 डॉलर ▼ 0.50 डॉलर

एक नज़र

अनिल अंबानी मुंबई में ईडी के सामने हुए पेश

रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी गुरुवार को मुंबई में येस बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर और अन्य के खिलाफ धन-शोधन मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अंबानी सुबह करीब साढ़े नौ बजे ईडी के कार्यालय बलार्ड एस्टेट पहुंचे। अंबानी को पहले सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए थे। ईडी ने उन्हें 30 मार्च को फिर पेश होने के लिए कहा है। इस बीच, ईडी ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्र को येस बैंक पीएमएल मामले में 21 मार्च को तलब किया है।

विमान ईंधन, कुछ रसायनों के आयात नियम सरल

सरकार ने जस्ते के अपशिष्ट और मिट्टी का तेल (नाफ्था) समेत कुछ जिंसों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। साथ ही विमानन प्रशिक्षण केंद्रों (फ्लाइंग क्लब) को कुछ शर्तों के साथ विमान ईंधन के आयात की भी खुली छूट दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक फ्लाइंग क्लबों को छोड़ कर विमान ईंधन के अन्य उपभोक्ता इसका आयात सरकारी तेल कंपनियों के माध्यम से कर सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि जस्ते के अपशिष्ट, हल्के नाफ्था, भारी नाफ्था और नाफ्था की शेष पूरी श्रृंखला के साथ विमान ईंधन के आयात को लेकर नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन किया गया है।

मप्र में शुक्रवार को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एन पी प्रजापति को शुक्रवार को सदन का विशेष सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह पूरी प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि अगर कांग्रेस के 16 बागी विधायक शक्ति परीक्षण की कार्यवाही में शामिल होना चाहें तो उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। पृष्ठ 4

रेल यात्रियों की आवाजाही पर कोरोनावायरस का असर

चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे के लिए कोरोनावायरस रंग में भंग डालने वाला साबित हो रहा है। इस वर्ष मार्च महीने में मार्च 2019 की तुलना में आरक्षित यात्रियों व रेलवे की कमाई में क्रमश: 29 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की कमी आई है। रेलवे ने इस सप्ताह 155 जोड़ी ट्रेनें रद्द की हैं। यह कोविड-19 के प्रसार पर काबू करने के लिए किया गया है। भारतीय रेल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 7 दिनों में यात्रियों की संख्या में 55 प्रतिशत और कमाई में 47 प्रतिशत कमी आई है। पृष्ठ 4

इस वर्ष देश में मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद

निराशाजनक खबरों के बीच मौसम के संबंध में कुछ अच्छी खबर है। मौसम के नवीनतम पूर्वानुमान से पता चलता है कि मॉनसून से पहले के महीनों के दौरान तथा देश में मॉनसून की शुरुआत होने के बाद भी यानी मई, जून और जुलाई महीने में खौफनाक अल नीनो 'तटस्थ' रहने के आसार हैं। अल नीनो मौसम की वह दशा है जिसे भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की गति बाधित करने वाला माना जाता है। अल-नीनो के तटस्थ रहने से इस वर्ष देश में मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। पृष्ठ 6

व्यापार गोष्ठी

महामारी से निपटने को कितने तैयार हम?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या कोरोना संकट के बीच रोजगार पर गिरेगी गाज

www.bshindi.com **पर राय भेजें।** आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

जरूरी सामान की जमाखोरी रोकने के लिए भरोसा बहाल करे सरकार? हां **80.00%** नहीं **20.00%**

कोरोना से बंद जैसे हालात

हवाई, रेल और सड़क परिवहन पर असर, कई राज्यों में मॉल-रेस्टोरेंट भी रहेंगे बंद

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली/मुंबई, 19 मार्च

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामले से कई राज्यों में पाबंदियां लगाए जाने के कारण बंदी (लॉकडाउन) की स्थिति पैदा हो गई है। देश में कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या चार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोनावायरस से चौथी मौत पंजाब में हुई है। देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 173 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है। साथ ही जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और चिकित्सा पेशेवरों को छोड़कर, 65 साल से अधिक उम्र के अन्य नागरिकों को घर में रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। फार्मा विभाग और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो मास्क और सैनेटाइजर के लिए अधिक कीमत वसूल रहे हैं।

भारत ने 22से 29 मार्च तक देश में सभी व्यावसायिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय रेल ने अनावश्यक यात्रा टालने के लिए रोगियों, छात्रों और दिव्यांगजन श्रेणी के लोगों को छोड़ कर सभी रियायती टिकटें 20 मार्च आधी रात से अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया है। 84 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे ने शुक्रवार से मुंबई में वातानुकूलित लोकल ट्रेनों की सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। केरल सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि वह अपने मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में 25 फीसदी की कटौती करेगी।

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है और शेष कर्मचारी तीन समूहों में अलग-अलग अवधि के लिए रोजाना कार्यालय आएंगे। कार्मिक मंत्रालय ने आज एक आदेश में इस सिलसिले में निर्देश जारी किए। कई राज्यों ने मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को बंद करने का निर्देश दिया है। राजधानी दिल्ली में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभाओं में 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर रेस्तरां बंद कर दिए गए हैं लेकिन होम डिलिवरी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों को अलग रहने को कहा गया है उन्हें नियमों का अनुपालन करना चाहिए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमितों को पृथक रखने के लिए दिल्ली सरकार के पास 768 बिस्तर हैं, जिनमें से 57 भर गए हैं।

इस बीच कश्मीर घाटी सहित देश के कई हिस्से बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल, प्रशासन कई इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा रहा है और श्रीनगर शहर में सभी सार्वजनिक वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजाब और दिल्ली भी आंशिक रूप से बंद जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

पंजाब सरकार ने शुक्रवार आधी रात से सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं स्थगित करने और लोगों के जमावड़ों में व्यक्तियों की संख्या 20 से कम करने के अलावा विवाह भवन, होटल और रेस्त्रां आदि बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, होम डिलिवरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। मुंबई में टिफिन सेवा प्रदान करने वाले (डिब्बावाले) ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार से 31 मार्च तक अपनी सेवाएं स्थगित कर दी है। दक्षिण दिल्ली के सुंदर नगर मार्केट को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

- संक्रमितों की संख्या 173 पहुंची, मरने वालों की संख्या चार हुई
- विदेशी उड़ानों के भारत आने पर प्रतिबंध
- मुंबई में एसी लोकल का परिचालन बंद
- जम्मू और उधमपुर में सभी दुकानें बंद
- रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, रियायती टिकट भी बंद
- बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रहने की सलाह

■ संबंधित खबरें : पृष्ठ 12

रविवार को देश भर में लगेगा 'जनता कर्फ्यू'

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 19 मार्च

- प्रधानमंत्री ने जनता से की सुबह 7 से रात 9 बजे तक घरों में ही रहने की अपील
- लोगों से अनावश्यक खरीदारी और जमाखोरी से दूर रहने को कहा
- आवश्यक वस्तुओं और आपूर्ति की कमी नहीं होने देने का आश्वासन
- कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए वित्त मंत्री की अगुआई में समिति गठित

रविवार 22 मार्च को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग पूरा देश बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात अपने संबोधन में देशवासियों से आग्रह किया कि कोरोनावायरस की महामारी को देखते हुए रविवार को सुबह 7 से रात 9 बजे तक सभी अपने घरों में ही रहें और बाहर नहीं निकलें। उन्होंने इसे 'जनता कर्फ्यू' का नाम दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक मेलजोल में कमी की जरूरत बताते हुए कहा कि जिन देशों में इसका असर ज्यादा हुआ है, वहां शुरुआती दिनों के बाद ही बीमारी का विस्फोट हुआ और संख्या अचानक बढ़ गई। जब विकसित देशों पर ऐसी मार पड़ी है तो भारत पर भी असर होना लाजिमी है। लेकिन इस असर को कम करने के लिए बाहर निकलना और घुलना-मिलना भी कम करना होगा। उन्होंने कहा, 'इसके लिए मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करें। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में ही रहें और बाहर नहीं निकलें। यह जनता के लिए जनता के द्वारा कर्फ्यू होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आसपास का हरेक व्यक्ति इस कर्फ्यू का पालन करे।'

मोदी ने कहा कि उस दिन स्वास्थ्य सेवा, दैनिक आपूर्ति, मीडिया जैसी सेवाएं जारी रहेंगी और उनमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस दौरान घरेलू सहायक और कामगार भी अगर छुट्टी लें तो उनका वेतन नहीं काटा जाए। (शेष पृष्ठ 14 पर)

शेयर बाजार में गिरावट बरकरार

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 19 मार्च

- 7,833 तक फिसलने के बाद 8,263 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी
- सेंसेक्स 581 अंक की गिरावट के साथ 28,288 पर बंद

शेयर बाजार में गिरावट बनी हुई है और बेंचमार्क निफ्टी आज 8,000 के नीचे आ गया, लेकिन कारोबार के दौरान एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईटीसी जैसे दमदार शेयरों के अच्छे प्रदर्शन से काफी हद तक वापसी करने में मदद मिली। सुबह के कारोबार में निफ्टी 7,833 तक फिसल गया था और कारोबार की समाप्ति पर 205 अंक नीचे 8,263 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 26,714 के स्तर पर आने के बाद 581 अंक की गिरावट के साथ 28,288 पर बंद हुआ।

विशेषज्ञों ने कहा कि अगर वैश्विक बिकवाली जारी रही तो बाजार में सुधार की संभावना कम होगी। कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है और अधिकांश बाजार गिरावट पर बंद हुए। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट देखी गई। विभिन्न देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों की ओर से पिछले कुछ दिनों में प्रोत्साहन के कई उपाय किए जाने के बावजूद निवेशकों में भरोसा नहीं बढ़ा है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल रिसर्च के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, 'नीति निर्माताओं ने पहले से प्रोत्साहनों पर काफी खर्च कर चुके हैं। मौद्रिक नीति में ढील देने के उपाय भी कई बार किए जा चुके हैं लेकिन इन सबका अस्थायी असर पड़ा है।'

विशेषज्ञों ने कहा कि हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 750 अरब यूरो की प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम की घोषणा की है, वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी पूंजी बाजार की मदद का ऐलान किया है। भारत में भी उपाय किए गए हैं लेकिन अन्य देशों की तुलना में वह कम हैं।

इडलवाइस ने एक नोट में कहा है, 'भारत को ऐसे समय में विश्वव्यापी महामारी का सामना करना पड़ रहा है जब अर्थव्यवस्था में नरमी चल रही है। ऐसे में तेजी से नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। मौजूदा हालात में दरों में कटौती में देरी भारी पड़ सकती है और तेल पर कर बढ़ाना और रुपये को सहारा देना उचित नहीं है।'

बाजार के भागीदारों ने कहा कि 7,833 के स्तर से निफ्टी में सुधार होनो महत्त्वपूर्ण है। कोटक सिक्योरिटीज में तकनीकी शोध विश्लेषक श्रीकांत चौहान ने कहा, '7,900 और 7,800 के स्तर का विशेष महत्त्व है। विमुद्रीकरण के दिन निफ्टी 7,890 के स्तर पर था। ऐसे में हम इसके 8,800 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 7,800 से नीचे जाने पर यह 7,500 या 7,300 पर आ सकता है।'

विदेशी निवेशकों ने पिछले एक महीने में 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिकवाली की है। करीब 1,206 शेयर 52 हफ्ते के अपने निचले स्तर को छुआ और 442 शेयर में लोअर सर्किट लगा। सेंसेक्स की दो-तिहाई शेयर गिरावट पर बंद हुए। बजाज फाइनैंस में सबसे ज्यादा 10.24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। आईटीसी का शेयर 7.5 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ।

उद्योग को राहत पैकेज देने की तैयारी

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 19 मार्च

- एनपीए नियमों और कर में राहत पर विचार
- कंपनियों को ऋण के भुगतान में मिलेगी राहत
- कुछ क्षेत्रों के लिए कर में फौरी छूट देने पर विचार
- आने वाले दिनों में हो सकती उपायों की घोषणा

कोरोनावायरस की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार उद्योग जगत को राहत पैकेज देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत कई तरह के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इनमें बैंकों द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण के नियमों में ढील और कोरोनावायरस की मार से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों जैसे उड्डयन और आवाभगत आदि को कर में छूट शामिल है। परिसंपत्ति वर्गीकरण के नियमों में ढील देने से कंपनियां देर से ऋण का भुगतान कर सकेंगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में विभिन्न मंत्री संबंधित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों की घोषणा कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कई स्तरों में इस बारे में चर्चा हो रही है। विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे नियामकों के साथ भी सलाह-मशविरा चल रहा है। मंत्री भी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव दे रहे हैं। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऋण के भुगतान में राहत देने पर सक्रियता के साथ विचार किया जा रहा है। खास अवधि के लिए कंपनियों को ऋण के भुगतान में छूट दी जाएगी और बैंक परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के नियमों में ढील देंगे। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर 90 दिन में ऋण की किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो इसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसमें जितनी अवधि की छूट दी जाएगी, उस दौरान बैंक बकाया ऋण को एनपीए की श्रेणी में नहीं डाल पाएंगे। अधिकारी ने कहा कि इस बारे में अभी आंतरिक स्तर पर और आरबीआई के साथ चर्चा चल रही है कि क्या इस तरह की छूट केवल सूक्ष्म, लघु एवं मझोली कंपनियों को दी जानी चाहिए या बड़ी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ऋण के भुगतान में यह छूट किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं होगी।

प्रभावितों को बेरोजगारी भत्ता

केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को बेरोजगारी लाभ देने की योजना बना रही है, जिनकी नौकरियां कोरोनावायरस महामारी की वजह से गई हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में इस तरह की पहल की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना में शामिल कर्मचारियों को सरकार अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी बीमा मुहैया कराती है और अब इसमें कोरोनावायरस के कारण बेरोजगार हुए कामगार भी शामिल किए जाएंगे। पृष्ठ 4

संकट में विमानन उद्योग, वेतन में कटौती

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 19 मार्च

- इंडिगो ने वेतन में 10 से 25 फीसदी तक कटौती की घोषणा की
- सरकार कर रही राहत पैकेज देने पर विचार
- कई विमानों का परिचालन बंद

मुश्किल दौर से गुजर रहीं भारतीय विमानन कंपनियों को उड़ानों में कटौती, कर्मचारियों की छंटनी तथा वेतन में कटौती जैसे कड़े कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

लगभग सभी विमानन कंपनियों ने अपने परिचालन में काफी कटौती की है और बुकिंग कम होने तथा बुकिंग रद्द होने की वजह से विमानों को खड़ा करना पड़ रहा है। विमानन क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के मुख्य वित्त अधिकारियों के साथ सात घंटे की लंबी बैठक की। सरकार के अधिकारियों ने कहा कि विमानन ईंधन में कर छूट, पार्किंग और लैंडिंग शुल्क को छह महीने माफ करना और तेल कंपनियों को भुगतान तीन महीने के लिए टालने जैसे प्रोत्साहन उपाय हो सकते हैं।

इंडिगो ने वरिष्ठ प्रबंधन, पायलटों और क्रू सदस्यों के वेतन में बड़ी कटौती करने का निर्णय किया है। इंडिगो के मुख्य कार्याधिकारी रनजय दत्ता ने कहा कि विमानन उद्योग को बचाने के लिए ऐसा करना अपरिहार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि वे लागत में कटौती की योजना पर काम कर रहे हैं और कर्मचारियों के वेतन में पांच फीसदी की कटौती हो सकती है।

गोएयर ने कर्मचारियों को बारी-बारी से बिना वेतन के अवकाश पर जाने की योजना पेश की, वहीं विदेशी पायलटों के अनुबंध निलंबित कर रही है।

दत्ता भी अपना वेतन 25 फीसदी कम लेने का निर्णय किया है। उन्होंने कर्मचारियों को लिखा, 'उद्योग पर कोरोनावायरस के गंभीर प्रभाव का डर है। इस परिदृश्य में राजस्व कम होगा और उद्योग को बचाने के लिए हरसंभव उपाय करने होंगे। हमें सुनिश्चत करन होगा कि हमारे पास नकदी कम न हो।'

इंडिगो के आठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष के वेतन में भी 20 फीसदी की कटौती होगी, वहीं उपाध्यक्ष और पायलटों के वेतन में 10 फीसदी की कटौती की जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने करीब 60 विमानों का परिचालन बंद किया है। उद्योग के अधिकारियों और बाजार के विश्लेषकों की इस पर नजर रहेगी कि स्पाइसजेट मौजूदा स्थिति में सुधार लाने में सक्षम होगी या नहीं। कम नकदी और बोइंग 737 मैक्स को परिचालन से हटाने की वजह से स्पाइसजेट को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। परिदृश्य कमजोर होने से स्पाइसजेट को पैसे की सख्त जरूरत है।

उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, 'मुझे पता नहीं कि स्पाइसजेट को परिचालन जारी रखने के लिए पूंजी मिलेगी या नहीं। वह बोइंग से अंतरिम तौर पर कुछ नकदी जारी करने का अनुरोध कर सकती है।'

खबरों में रहे स्टॉक

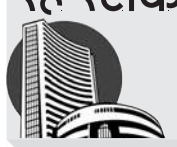

आईटीसी

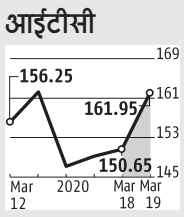

शेयरधारकों को तय लाभांश भुगतान कर बाद लाभ के 80 से 85 फीसदी पर

₹ 150.65 पिछला बंद भाव
₹ 161.95 आज का बंद भाव
▲ 7.50 %

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस

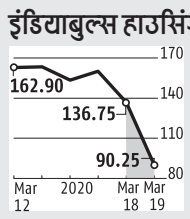

ए समूह में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 136.75 पिछला बंद भाव
₹ 90.25 आज का बंद भाव
▼ 34.00 %

मारुति सुजूकी इंडिया

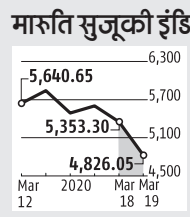

कोविड-19 के फैलने से वाहन क्षेत्र पर दिखेगा नकारात्मक प्रभाव

₹ 5,353.30 पिछला बंद भाव
₹ 4,826.05 आज का बंद भाव
▼ 9.85 %

भारती इन्फ्राटेल

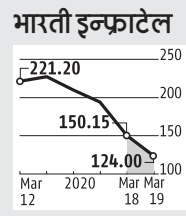

एजीआर बकाये पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 36 फीसदी गिरा शेयर

₹ 150.15 पिछला बंद भाव
₹ 124.00 आज का बंद भाव
▼ 17.42 %

इमामी

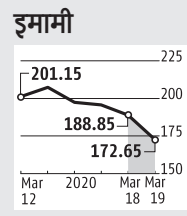

खुले बाजार से 300 रुपये अधिकतम मूल्य पर पुनर्खरीद को मंजूरी

₹ 188.85 पिछला बंद भाव
₹ 172.65 आज का बंद भाव
▼ 8.58 %

संक्षेप में

एचसीएल टेक ने आपात योजना पर काम शुरू किया

भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के नोएडा परिसर में एक कर्मचारी के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने पर कंपनी ने सभी जगहों पर अपनी आपात योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अधिक से अधिक कार्य घर से करने और सामाजिक दूरी बनाने पर जोर दिया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक यात्रा परामर्श भी जारी किया है जिसमें अगली सूचना तक सभी गैर-जरूरी यात्रा को टालने और सुरक्षा संबंधी उपायों पर अमल करने के लिए कहा गया है। *बीएस*

आरआईएल का घर से काम करने पर जोर

भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों को 31 मार्च तक घर से काम करने का निर्देश दिया है। हालांकि कंपनी अपने उपभोक्ता केंद्रित कारोबार जैसे अस्पताल, खुदरा स्टोर एवं दूरसंचार को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ आगे बढ़ाएगी। *एजेंसियां*

कोरोनावायरस का प्रभाव

होटलों और एयरलाइनों में संकट

कृष्णकांत
मुंबई, 19 मार्च

यात्रा एवं आतिथ्य सेवा क्षेत्र को कर्ज मुहैया कराने वाले बैंकों को कोरोनावायरस से आर्थिक अनिश्चितता गहराने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र की 65 सूचीबद्ध कंपनियों पर सितंबर 2019 के अंत में लगभग 30,500 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में सालाना आधार पर 37.2 प्रतिशत ज्यादा है। सितंबर 2018 के अंत में इन कंपनियों का कुल बकाया लगभग 22,200 करोड़ रुपये था।

होटल कंपनियां सबसे बड़ी कर्जदार हैं जिसके बाद विमानन कंपनियां शामिल हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के नमूने में शामिल कुल उधारी के लगभग 50 प्रतिशत में इंडियन होटल्स, शैलेट होटल्स, लेमन ट्री होटल्स और एशियन होटल्स (नॉर्थ) जैसी होटल श्रृंखलाओं का योगदान है। इस विश्लेषण में एयर इंडिया और बंद हो चुकी जेट एयरवेज, कॉक्स ऐंड किंग्स तथा किंगफिशर एयरलाइंस जैसी बड़ी गैर-सूचीबद्ध कर्जदार शामिल नहीं हैं।

अहम विमानन कंपनियों और होटल श्रृंखला की उधारी और बैलेंस शीट

कंपनी	कुल कर्ज	आईसीआर	सकल लिवरेज अनुपात
स्पाइसजेट	8794.3	3.9	-10.4
कॉफी डे इंटर.*	6547.4	2.3	2.6
इंडियन होटल्स	3503.2	3.3	0.9
महिंद्रा हॉलिडेज	1772.2	4.8	9.2
शाले होटल्स	1370.1	2.7	0.9
लेमन ट्री होटल	1285.1	1.7	1.6
एशियन होटल्स (एन)	1183.3	0.6	1.7
एशियन होटल्स (डब्ल्यू	782.6	1.5	7.7
ईआईएच	687.4	6.5	0.2
इंटरग्लोब एविएशन	622.2	3.9	0.1
सभी 65 कंपनियां	30495.8	3.4	0.9

नोट : ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) अपप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान
सकल लिवरेज यानी कर्ज-इक्विटी अनुपात सितंबर 2019 के आखिर में (पहली छमाही)
सभी आंकड़े व अनुपात मार्च 2019 की तिमाही के, कर्ज करोड़ रुपये में
स्रोत : कैपिटालाइन। संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

एयरलाइन ऑपरेटर स्पाइसजेट इस उद्योग में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है। एयरलाइन पर सितंबर 2019 के अंत में लगभग 8,800 करोड़ रुपये का कुल बकाया था, जो एक साल पहले 1217 करोड़ रुपये पर था। इसके बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेज का स्थान है जिस पर सितंबर 2019 के अंत तक कुल बकाया ऋण 6,500 करोड़ रुपये था, जो एक साल पहले के 4,410 करोड़ रुपये की तुलना में ज्यादा है। इसी तरह इंडियन होटल्स (3,500 करोड़ रुपये) और महिंद्रा होलिडेज (1,770 करोड़ रुपये) पर बड़ा कर्ज है।

एयरलाइनों को मौजूदा समय में कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए संकट से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने हवाई यात्रा प्रतिबंधित कर दी है और यात्री स्वयं ही अपनी छुट्टियों की योजनाएं रद्द कर रहे हैं। हवाई यात्रा में लंबे समय तक गिरावट से स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि उस पर भारी भरकम कर्ज है।

तुलनात्मक रूप से, बाजार दिग्गज इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करती है) का कुल बकाया ऋण वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही के अंत तक लगभग 622 करोड़ रुपये था, जो 6200 करोड़ रुपये के नेटवर्थ से संबंधित था। इससे उसे उद्योग में मंदी की स्थिति में स्वयं को बचाए रखने में मदद मिली है।

हॉस्पिटैलिटी या होटल उद्योग में, लेमन ट्री होटल्स, एशियन होटल्स (नॉर्थ) और एशियन होटल्स (वेस्ट) जैसी छोटी श्रृंखलाएं इंडियन होटल्स, ईआईएच और शैलेट होटल्स जैसी बड़ी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कोरोनावायरस के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होती दिख रही हैं। वित्त वर्ष 2020 के पहले 9 महीनों में इन छोटी होटल श्रृंखलाओं का ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) बड़ी और प्रतिष्ठित होटल कंपनियों की तुलना में काफी कम था। आईसीआर कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता का मापक है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 के अंत में 1,285 करोड़ रुपये की कुल उधारी दर्ज करने वाली लेमन ट्री होटल्स का आईसीआर 1.6 गुना जबकि इंडियन होटल्स के लिए यह 3.3 गुना और ईआईएच के लिए 6.5 गुना रहा।

वित्तीय नतीजों के लिए कंपनियों को मोहलत

समी मोडक
मुंबई, 19 मार्च

- बाजार नियामक सेबी ने कहा, वायरस के प्रसार के कारण अस्थायी छूट जरूरी
- मार्च तिमाही और पूरे साल के वित्तीय नतीजों के लिए समयसीमा में क्रमशः 45 दिन व 30 दिन का विस्तार कर इसे जून 2020 कर दिया गया है
- शेयरधारिता पैटर्न के बारे में जानकारी देने की आखिरी तारीख अब 21 अप्रैल के बजाय 15 मई होगी

सूचीबद्ध कंपनियों को वित्तीय नतीजे और शेयरधारिता के पैटर्न से जुड़े खुलासे आदि के लिए बाजार नियामक सेबी ने समयसीमा में छूट दी है। सेबी ने गुरुवार को यह छूट दी। दुनिया भर में कोरोनावायरस के प्रसार के कारण अप्रत्याशित अवरोध का सामना कर रहे भारतीय कंपनी जगत को इस कदम से राहत मिलेगी।

सेबी ने एक बयान में कहा, वायरस के प्रसार के कारण सूचीबद्ध कंपनियों को अनुपालन की अनिवार्यताओं से अस्थायी राहत देना जरूरी हो गया था। मार्च तिमाही और पूरे साल के वित्तीय नतीजों के लिए समयसीमा में क्रमशः 45 दिन व 30 दिन का विस्तार कर जून 2020 कर दिया गया है। शेयरधारिता पैटर्न के बारे में जानकारी देने की आखिरी तारीख अब 21 अप्रैल के बजाय 15 मई होगी।

इसके अलावा कंपनियों को कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, अनुपालन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों से जुड़े बयान जमा कराने में भी छूट दी गई है। विशेषज्ञों ने कहा, यह जरूरी था क्योंकि लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण कंपनियां काफी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर के. कोतलाव ने कहा, हाल के हफ्तों में कई कंपनियों ने खुद ही कदम उठाते हुए कर्मियों को घर से काम करने की इजाजत देने की घोषणा की है। सेबी की तरफ से दी घई छूट उन्हें मौजूदा कारोबारी अनिवार्यता पर ध्यान देने में मददगार होगी।

अमेरिकी एसईसी समेत दुनिया के कई नियामकों ने हाल के हफ्तों में ऐसी ही छूट प्रदान की है। एलऐंडएल पार्टनर्स के पार्टनर हरीष कुमार ने कहा, कंपनी प्रशासन से जुड़े पहलू पर अनुपालन में सूचीबद्ध इकाई के कई विभाग के बीच सामंजस्य की जरूरत होती है, साथ ही बोर्ड बैठक व कमेटी की बैठक भी करनी होती है। कोरोनावायरस के कारण पैदा हुई मौजूदा स्थिति ने विभिन्न उद्योग में लोगों के कामकाज को प्रभावित किया है, ऐसे में सेबी की तरफ से दी गई छूट निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है।

विशेषज्ञों ने कहा, कोरोनावायरस के प्रसार का कारोबार पर पड़ने वाले असर के बारे में कंपनियों को अपने निवेशकों को सूचित करने की हरसंभव कोशिश करनी चाहिए।

साइरिल अमरचंद मंगलदास की पार्टनर श्रुति राजन ने कहा, वैश्विक स्तर पर नियामकों ने कंपनियों को कारोबार, आय, राजस्व आदि पर पड़ने वाले कोरोना केअसर के बारे में खुलासा करने को प्रोत्साहित किया है।

विशेषज्ञों ने कहा, कोविड से पड़ने वाले असर के बारे में कंपनियों को खुलासा करने के लिए बाजार नियामक ने अभी आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन कंपनियों की तरफ से स्वतः कदम उठाए जाने से निवेशकों की अवधारणा सुधारने में मदद मिलेगी, जो शेयर बाजारों में तेज गिरावट से प्रभावित हुई है।

सेवानिवृत्त लोगों की बचत खतरे में

जश कृपलानी
मुंबई, 19 मार्च

येस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड में सीधे तौर पर निवेश करने वाले सेवानिवृत्त लोगों की जीवन भर की बचत खतरे में पड़ गई है क्योंकि इस बैंक की पुनर्गठन योजना के तहत एटी-1 बॉन्ड को बट्टेखाते में डालने का निर्णय लिया गया है।

66 वर्षीय सेवानिवृत्त विंग कमांडर देव ने कहा, 'एटी-1 बॉन्ड को पूरी तरह बट्टेखाते में डालना हमें जीवन भर के लिए दंडित करने जैसा है क्योंकि हमने सभी करों का भुगतान करने के बाद इस रकम को अपने बुढ़ापे के लिए रखा था। येस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर (आरएम) को अपना लक्ष्य पूरा करना था और इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बचत खाताधारकों को भी आक्रामक तरीके से इस बॉन्ड की बिक्री की जबकि मैंने स्पष्ट तौर पर बताया था कि बैंक में सावधि जमा जैसी सुरक्षित योजनाएं मेरी प्राथमिकता हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया था कि यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित है।'

एक आकलन के अनुसार, इन बॉन्डों में व्यक्तिगत निवेशकों का निवेश 1,000 करोड़ रुपये है। येस बैंक के एटी-1 बॉन्ड के निवेशकों में अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। इसमें पूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों से लेकर आईटी क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं।

अधिकांश संस्थागत बॉन्डधारकों के बदले ऐक्सिस ट्रस्टी द्वारा बंबई उच्च न्यायालय का रुख किए जाने के बाद व्यक्तिगत बॉन्डधारक भी उच्च न्यायालय में शिकायत करने की योजना बना रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ऐक्सिस ट्रस्टी बॉन्डधारकों को अपनी दलील पूरी करना अभी बाकी है। साथ ही येस बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वित्त मंत्रालय को भी अपना पक्ष रखना बाकी है।

व्यक्तिगत बॉन्डधारकों ने आरोप लगाया है कि बैंक के रिलेशंस मैनेजर ने उन्हें गुमराह करते हुए इस बॉन्ड की बिक्री की थी। येस बैंक के एटी-1 बॉन्ड को बट्टेखाते में डाले जाने के कारण अब वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उनकी जीवन भर की बचत खतरे में है।

आर्सेलरमित्तल यूरोप में घटाएगी उत्पादन

आर्सेलरमित्तल ने कहा है कि उसने यूरोप में उत्पाद घटाने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा, 'कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप और कई यूरोपीय देशों में उसके प्रभाव को देखते हुए कंपनी ने उत्पादन घटाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्पादन को मांग के अनुरूप बनाया जाएगा।' हजीरा इस्पात संयंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। *एजेंसियां*

टुडे होम्स की दिवालिया प्रक्रिया में खामी : यूवीएआरएसी

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 19 मार्च

दिल्ली की यूवी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (यूवीएआरसी) एक नए संघर्ष से जूझ रही है। आईबीसी प्रक्रिया के तहत दूरसंचार कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस टेलीकॉम (16,000 करोड़ रुपये की बोली) और एयरसेल के लिए सबसे बड़ी बोलीदाता बनने के बाद यूवीएआरसी सुर्खियों में आ गई थी।

ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस सप्ताह टुडे होम्स नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) से संपर्क साधा। टुडे होम्स नोएडा एक रियल एस्टेट कंपनी है जो अपनी पेशकश (वह दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए दो बोलीदाताओं में से एक थी) पर पुनर्विचार और आईबीसी के प्रावधानों के कथित उल्लंघन की वजह से लेनदारों की समिति (सीओसी) दोबारा मतदान की मांग कर रही है। यूवीएआरसी ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को यह भी बताया कि अगर वह समाधान तलाशने में विफल रही तो उसके पास एनसीएलटी या इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की शरण में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।

इस मामले में सीओसी में नोएडा में 18 टावरों जुड़े 1757 आवासीय फ्लैट मालिक और 21 वाणिज्यिक परिसंपत्तियां शामिल हैं और लेनदारों के तौर पर कोई बैंक शामिल नहीं है। यह परियोजना 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन 2019 में एनसीएलटी ने कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू किए जाने के लिए आवेदन स्वीकार किया था, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी परियोजना पूरी करने और घर मालिकों को सभी फ्लैट सौंपने में सफल नहीं रही थी।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को दो प्रस्ताव मिले, जिनमें एक यूवीएआरसी और दूसरा रियल एस्टेट डेवलपर वन ग्रुप से था और कई दौर की चर्चाओं के बाद इन प्रस्तावों को वोटिंग के लिए रखा गया था। वन ग्रुप के प्रस्ताव को शामिल किया गया। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल रविंदर कुमार मिंत्री के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को इस संबंध में भेजे गए ईमेल संदेश का अभी कोई जवाब नहीं मिला है।

यूवीएआरसी ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को भेजे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि आईबीसी की धारा 30 (3)(बी) के तहत परिचालन लेनदार को भुगतान परिसंपत्ति की परिसमापन वैल्यू से कम नहीं हो सकता। इस मामले में, एकमात्र सुरक्षित परिचालन लेनदार नोएडा अथॉरिटी है, क्योंकि उसे कंपनी की परिसंपत्तियों पर पहला अधिकार है। हालांकि यूवीएआरसी को घर खरीदारों से पता चला कि मंजूर की गई योजना इस मानदंड को पूरा नहीं करती। यूवीएआसरी ने कहा, इस बात की सूचना दी गई है कि परिसमापन कीमत 45 से 50 करोड़ रुपये है जबकि मंजूर की गई योजना में 4 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है, जो काफी कम है और उसे मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह आईबीसी के नियमों के खिलाफ है। यूवीएआरसी के सूत्रों ने कहा, हमने नोएडा अथॉरिटी को 30 करोड़ रुपये या परिसमापन कीमत (जो भी ज्यादा हो) देने की पेशकश की थी। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के फैसले का मतलब यूवीएआरसी को बड़ा नुकसान है, जिसे कंपनी ने एक अलग पत्र के जरिए नोएडा अथॉरिटी के सामने रखा था।

दूसरा, हमने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को बताया था कि वोटिंग प्रक्रिया में खामी के कारण सिर्फ 52 फीसदी घर खरीदार ही मतदान में सक्षम थे। यूवीएआरसी का तर्क है कि आईबीसी की धारा 25 ए घर खरीदारों को व्यक्तिगत तौर पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान का विकल्प नहीं देता। यह देखते हुए कि घर खरीदारों को व्यक्तिगत तौर पर मतदान का विकल्प नहीं दिया गया, लिहाजा इस प्रक्रिया से हासिल हुए मतदान के अनुदेश अवैध हैं।

तीसरा, घर खरीदारों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यूवीएआरसी ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को कहा था कि घर खरीदारों को सही तरीके से सूचित नहीं किया गया, लिहाजा वे सही फैसला नहीं ले पाए। यूवीएआरसी की योजना के तहत घर खरीदारों को परियोजना पूरी करने के लिए 289 रुपये प्रति वर्गफुट अतिरिक्त चुकाने थे।

विश्वव्यापी कोरोनावायरस महामारी का असर

एलआईसी के 2 लाख करोड़ रु. स्वाहा

दीपक कोरगांवकर और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 19 मार्च

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में कैलेंडर वर्ष 2020 में अब तक 32 फीसदी की गिरावट आई है, जिससे सार्वजनिक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा की किस्मत पर काफी असर पड़ा है और ढाई महीने में कंपनी को अपने निवेश पर 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इक्विटी में बड़ा निवेश करने वाली कंपनी के तौर पर मशहूर इस बीमा कंपनी का कई सूचीबद्ध कंपनियों में खासा निवेश है। एलआईसी के निवेश पर ऐसे समय चोट पड़ी है जब सरकार स्टॉक एक्सचेंजों पर एलआईसी को सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है, जो कानून में बदलाव व नियामकीय मंजूरी पर निर्भर करेगा।

दिसंबर 2019 की तिमाही में सूचीबद्ध कंपनियों में बीमा कंपनी के निवेश की वैल्यू 6.02 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब घटकर 3.99 लाख करोड़ रुपये रह गई है, जिसका मतलब यह है कि कंपनी का मार्क टु मार्केट नुकसान 2.03 लाख करोड़ रुपये यानी 34 फीसदी रहा है। यह अध्ययन एसऐंडपी बीएसई 500 इंडेक्स की 209 कंपनियों पर आधारित है, जिनमें एलआईटी की हिस्सेदारी दिसंबर 2019 की तिमाही में एक फीसदी से ज्यादा थी। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में इन कंपनियों की हिस्सेदारी 65 फीसदी है।

बैंक, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों समेत वित्तीय क्षेत्र में उनके निवेश पर भारी चोट पड़ी है और इस अवधि में एलआईसी की कुल वैल्यू में 30 फीसदी यानी 61,552 करोड़ रुपये की कमी दर्ज हुई है। तेल व गैस (30,041 करोड़ रुपये), सूचना प्रौद्योगिकी (16,112 करोड़ रुपये), सिगरेट निर्माता (15,117 करोड़ रुपये), धातु (13,549 करोड़ रुपये), ऑटोमोबाइल (12,896 करोड़ रुपये) और बुनियादी ढांचा (11,973 करोड़ रुपये) ऐसे क्षेत्र हैं जहां एलआईसी ने इस अवधि में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा गंवाए।

एलआईसी को नुकसान

कंपनी	हिस्सेदारी (फीसदी)	नुकसान (करोड़ रुपये
रिलायंस इंडस्ट्रीज	6.15	23,274
आईटीसी	16.25	15,117
आईसीआईसीआई बैंक	8.36	10,786
एसबीआई	9.13	10,580
एलऐंडटी	14.25	9,112
ऐक्सिस बैंक	9.02	8,293
टीसीएस	4.12	8,120
ओएनजीसी	9.48	8,068
कोल इंडिया	10.94	5,825
एचडीएफसी	4.21	5,749

निफ्टी-50 के शेयरों में 31 दिसंबर को एलआईसी की हिस्सेदारी
स्रोत : कैपिटालाइनप्लस संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

इक्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक व प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम ने कहा, सेवा से जुड़े क्षेत्र कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कृषि मोटे तौर पर अप्रभावित बना रहेगा, वहीं विनिर्माण पर उतना ही असर पड़ेगा जब वहां आपूर्ति से जड़े मसले होंगे। सेवा क्षेत्र में भी इसका असर अलग-अलग है। दूरसंचार हालांकि अप्रभावित रह सकता है, वहीं होटल, ट्रैवल व टूरिज्म इसकी चपेट में आएंगे। ये सभी चीजें एलआईसी समेत निवेशकों की किस्मत पर असर डालना जारी रखेगा। यह व्यवस्थागत मसला है।

क्रेडिट सुइस वेल्थ मैनेजमेंट के विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ महीने में (जब तक कि अर्थव्यवस्था पर कोराना के असर और भारतीय कंपनी जगत की किस्मत पर स्पष्टता नहीं आती) देसी व विदेशी निवेश प्रभावित होगा, जो भारतीय बाजारों पर असर डालेगा।

क्रेडिट सुइस वेल्थ मैनेजमेंट के इक्विटी शोध प्रमुख जितेंद्र गोहिल ने कहा, वायरस के डर और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और उभरते बाजारों में अपना निवेश घटा रहे हैं और भारत इसका अपवाद नहीं है। देसी इक्विटी निवेश अभी तक मजबूत रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति और उधारी वाली पोजिशन की बिकवाली को देखते हुए स्थिरता मुश्किल लग रही है।

ज्यादातर विश्लेषक इस पर सहमत हैं कि बाजार ने कोविड-19 यानी कोरोनावायरस के पूरे असर को समाहित नहीं किया है कि अर्थव्यवस्था और भारतीय कंपनी जगत पर इसका कितना असर होगा, लेकिन वे तीव्र सुधार से पूरी तरह इनकार नहीं कर रहे हैं जब स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। नोमूरा के विश्लेषकों ने मार्च 2021 के लिए निफ्टी-50 का लक्ष्य 11,030 पर बरकरार रखा है, जो मार्च 2022 के 15 गुने आय पर आधारित है।

डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 75 के पार

अनूप रॉय
मुंबई, 19 मार्च

भारतीय रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 75 के पार निकल गया, जिसने जोखिम भरे माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया जताई और इस प्रतिक्रिया में दुनिया भर की मुद्राओं ने डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज की। साथ ही कोरोनावायरस महामारी के गहराने के कारण तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज हुई।

डॉलर के मुकाबले रुपया 75.12 पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र में यह 1.010 फीसदी टूटा और करेंसी डीलर अब यह अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं कि यह गिरावट आखिर कहां थमेगी। कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 75.30 के निचले स्तर तक चला गया था। बुधवार को यह 74.26 पर बंद हुआ था। काफी कम कारोबार वाले बाजार में रुपये के लिए समस्या बढ़ रही है क्योंकि डॉलर की मामूली मांग या आरबीआई की तरफ से डॉलर की बिक्री विनिमय दर में बदलाव कर रही है।

फॉरेक्सससर्वे के प्रबंध निदेशक सत्यजित कांजीलाल ने कहा, हम अभी अज्ञात क्षेत्र में हैं। सभी मुद्राएं गिर रही हैं और रुपया भी टूट रहा है। लेकिन अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपये ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

अब एक चीज निश्चित है कि रुपये में गिरावट जारी रहेगी और आरबीआई के पास इसे थामने के लिए पर्याप्त रिजर्व तो है, लेकिन वह उसका इस्तेमाल हड़बड़ी में शायद नहीं करना चाहता।

अहम वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की माप करने वाला डॉलर इंडेक्स 102 के पार निकल गया, जो जनवरी 2013 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। जोखिम भरे माहौल के कारण ऐसा हुआ क्योंकि निवेशक यूएस ट्रेजरी जैसे सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपने निवेश की बिकवाली के लिए बढ़े। पाउंड साल 1985 के बाद के सबसे निचले स्तर तक गिरा। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी कई दशक के निचले स्तर पर चला गया जबकि कच्चे तेल की कीमत गिरकर 22 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई।

वास्तव में रुपये की गिरावट तेज थी, लेकिन उतना नहीं जितना कि क्षेत्र की अन्य मुद्राओं में गिरावट आई। इंडोनेशियाई रुपैया में सबसे ज्यादा गिरावट आई और यह 4.336 फीसदी टूटा, वहीं दक्षिण कोरियाई वॉन 3.117 फीसदी गिरा।

जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के ट्रेजरी प्रमुख गोपाल त्रिपाठी ने कहा, जोखिम भरा माहौल डॉलर इंडेक्स को बढ़ा रहा है। रुपया समेत उभरते बाजारों की मुद्राओं पर कुछ समय तक दबाव बना रहेगा।

आरबीआई के पास पर्याप्त भंडार होने के बावजूद रुपये में मौजूदा स्तर से शायद ही बहुत ज्यादा मजबूती आएगी जबकि उसे निश्चित तौर पर मजबूत होना चाहिए।

इस बीच, भारत का बॉन्ड प्रतिफल भी चढ़ा क्योंकि विदेशी निवेशकों ने स्थानीय बॉन्डों की बिकवाली की। 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 6.41 फीसदी पर बंद हुआ, जो एक दिन पहले 6.29 फीसदी पर बंद हुआ था। ऐसा तब हुआ जबकि आरबीआई ने बुधवार को द्वितीयक बाजार में 10,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीद कार्यक्रम का ऐलान किया था ताकि प्रतिफल नरम हो सके।

निराशाजनक माहौल में कर प्रोत्साहन चाह रहा बाजार

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 19 मार्च

बाजार के प्रतिभागियों की अवधारणा में सुधार की आखिरी कोशिश के तौर पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर, शेयर पुनर्खरीद और शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश पर कर हटाने की मांग हो रही है। कई प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर यह मांग की है। इन्फोसिस के पूर्व अधिकारी मोहनदास पई ने शेयर पुनर्खरीद पर कर हटाने की मांग की है। बुधवार को एक ट्वीट में उन्होंने कहा, निवेशकों ने 35 लाख करोड़ रुपये गंवा दिए हैं लेकिन खराब कर नीति कंपनियों की तरफ से खुले बाजार से शेयर पुनर्खरीद पर दंडित कर रही है।

सन फार्मा, इमामी, सुप्रीम पेट्रोकेम, थॉमस कुल और एसपी अपैरल ने हाल में पुनर्खरीद के प्रस्ताव की घोषणा की है। यह बाजार में आई बड़ी गिरावट की पृष्ठभूमि में हुई है। पुनर्खरीद पर बजट में प्रस्तावित 20 फीसदी कर कंपनियों को इस तरह की घोषणा से हतोत्साहित कर सकता है। पुनर्खरीद के तहत या तो खुले बाजार से शेयरों की पुनर्खरीद होती है या फिर टेंडर के जरिये। शेयर पुनर्खरीद से प्रति शेयर आय और इक्विटी पर रिटर्न सुधारने में मदद मिलती है।

फिलिपींस का बाजार धराशायी बाजार बंद होने का जोखिम

बीएस संवाददाता और एजेंसियां
मुंबई, 19 मार्च

दो दिन की असामान्य बंदी के बाद फिलिपींस के शेयरों में रिकॉर्ड 13.3 फीसदी की गिरावट ट्रेडिंग पर विराम लगाने के विवादास्पद कदम से जुड़ी जोखिम का संकेत देता है। जनवरी 2012 के बाद के निचले स्तर पर बंद होने से पहले फिलिपींस स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 24 फीसदी तक टूट गया, जो उसके मूल्यांकन को 11 साल के निचले स्तर पर ले आया। 27 अरब पेसो का राजकोषीय प्रोत्साहन कोरोनावायरस के प्रसार पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त नहीं होने की चिंता के बीच यह गिरावट ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती के केंद्रीय बैंक से फैसले से पहले आया।

पापा सिक्योरिटीज कॉर्प के रणनीतिकार एम क्रूज ने कहा, दो दिन की बंदी ने उन निवेशकों के लिए दरवाजा बंद कर दिया, जो वहां से निकासी के लिए बढ़ रहे थे। वहां से निकलने वाली रकम इकट्ठा हो गई और निवेशक भयभीत हो गए व आत्मविश्वास खो बैठे कि अपनी इच्छा के मुताबिक बाजार से कभी भी निकासी की जा सकती है, ऐसे में उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से इसे निकासी का मौका समझा।

इक्विटी, करेंसी और बॉन्ड बाजार मंगलवार से बंद होने शुरू हुए, जब सरकार ने सोमवार को राजधानी क्षेत्र में एक महीने तक कामकाज में बंदी का विस्तार करते हुए उसके दायरे में देश के मुख्य लूजॉन द्वीप को ला दिया, जो कम से कम 5.7 करोड़ लोगों का ठिकाना है।

फिलिपींस स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक और फिलइक्विटी फंड के मैनेजर विल्सन एसवाई ने कहा, हमें पता था कि वहां काफी बिकवाली होगी, जो विदेशी निवेशक करने जा रहे थे, लेकिन हमें बाजार खोलना पड़ा और दुनिया को दिखाना पड़ा कि डर के माहौल के बावजूद फिलिपींस की अर्थव्यवस्था चल रही है।

फिलिपींस स्टॉक एक्सचेंज ने गुरुवार को कहा कि एक्सचेंज अस्थायी तौर पर सर्किट के नियमों में बदलाव पर विचार कर रहा है ताकि बाजार के उतारचढ़ाव से निपटा जा सके।

कोरोना से प्रभावित अमेरिका पहले से ही मंदी में : बोफा

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 19 मार्च

बोफा सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोनावायरस से प्रभावित अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी में है, हालांकि उसे उम्मीद है कि यह चरण अल्पावधि वाला होगा और 2020 की तीसरी तिमाही में यह वापस पटरी पर आएगा। शोध फर्म को हालांकि लग रहा है कि नौकरियों का काफी नुकसान होगा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से सिर्फ राहत पैकेज तक सीमित नहीं रहने का अनुरोध किया है।

बोफा सिक्योरिटीज के अर्थशास्त्रियों ने कहा, हमारा मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई है और इस तरह से वह बाकी दुनिया में शामिल हो गई है। अब हमें उम्मीद है कि दूसरी तिमाही में यह अर्थव्यवस्था तिमाही दर तिमाही फिसलकर समायोजित सालाना दर 12 फीसदी तक आ जाएगी जबकि पहली तिमाही में महज 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। यह गिरावट हालांकि ज्यादा है, लेकिन हमारा मानना है कि यह अल्पावधि वाली होगी।

पूरे साल के लिए बोफा सिक्योरिटीज ने जीडीपी में 0.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान जताया है। फर्म का कहना है कि कोरोना के असर गहरे होंगे क्योंकि इस वजह से उसे नौकरियों में भारी कमी और संपत्ति के नुकसान की आशंका है।

कोरोनावायरस से प्रभावित कर्मचारियों को बेरोजगारी लाभ की पेशकश करेगा भारत

सोमेश झा
नई दिल्ली, 19 मार्च

केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को बेरोजगारी लाभ देने की योजना बना रही है, जिनकी नौकरियां कोरोनावायरस महामारी की वजह से गई हैं। यह अमेरिका जैसे कुछ देशों द्वारा उठाए गए कदमों की तर्ज पर है, जो कामकाजी लोगों को आपदा से बचाने की कवायद के लिए है।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना में शामिल कर्मचारियों सरकार अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी बीमा मुहैया कराती है, जिसमें कोरोनावायरस के कारण बेरोजगार हुए कामगार भी शामिल होंगे। ईएसआई भारत के औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्ववित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) करता है।

जुलाई 2018 से चल रही इस योजना के तहत बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को 3 महीने तक बेरोजगार रहने का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कर्मचारी इस योजना का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार उठा सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर बताया, 'श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस योजना को विस्तार देने और कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों को इसका लाभ देने पर विचार कर रही है।'

इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान पिछले 2 साल से मिल रहे औसत वेतन का 25 प्रतिशत नकद मिलता है। बहरहाल इसमें कर्मचारियों के लिए अहम शर्त यह है कि उन्ही कर्मचारियों के बेरोजगार होने पर यह लाभ मिलता है, जो ईएसआईसी के कम से कम दो साल से सदस्य हैं। जब जुलाई 2018 में इस योजना को पेश किया गया था, तब 10 लाख कर्मचारी इसके पात्र थे।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अनुमान लगाया है कि पूरी दुनिया में करीब 2.5 करोड़ लोग कोविड 19 के कारण बेरोजगार हो सकते हैं। इसमें अनुमान लगाया गया है कि कोरोनावायरस के कम प्रसार पर 53 लाख और ज्यादा होने प 247 लाख नौकरियां जा सकती हैं। आईएलओ के मुताबिक 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के समय 220 लाख लोगों की नौकरियां गई थीं।

भारत में भी कोरोनावायरस का असर महसूस किया जा रहा है। उदाहरण के लिए एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें कम की हैं और विमान खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने अपने पायलट और क्रू से वेतनरहित छुट्टी लेने को कहा है। इससे तत्काल प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में ट्रैवल और टूरिज्म से लेकर आतिथ्य सत्कार व खुदरा क्षेत्र तक शामिल हैं। भारत के आयात पर निर्भर क्षेत्र ऑटोमोबाइल और दवा क्षेत्र भी वैश्विक कारोबार बाधित होने की वजह से प्रभावित होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रभावित कर्मचारियों को बेरोजगारी बीमा देने की कवायद संभवत: देश के व्यापक क्षेत्रों में फैले कार्यबल के लिए पर्याप्त नहीं होगी। एक्सएलआरआई जमशेदपुर के मानव संसाधन प्रबंधन के प्रोफेसर केआर श्यामसुंदर ने कहा कि ईएसआईसी में निजी संगठित क्षेत्र के सिर्फ दो तिहाई कर्मचारी शामिल होते हैं और यह भारत के कुल 47 करोड़ कामगारों के करीब 0.2 प्रतिशत हैं।

सुंदर ने कहा, 'इस योजना की कवरेज बहुत कम है। यह कोरोनावायरस के होने वाले असर की संवेदनशीलता को प्रदर्शित नहीं करता, जिससे नौकरियां जा रही हैं। यह सार्वभौम बेरोजगारी योजना की जगह सरकार की एक कमजोर परिकल्पना है।'

उन्होंने कहा कि इस योजना के कड़े पात्रता मानक प्रतिरोध का काम करेंगे और संकट के समय में ठेके वाली नौकरियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को उद्योग संगठनों के साथ बात करनी चाहिए, जिससे व्यापक रूप ले लागू होने वाली बेरोजगारी योजना तैयार की जा सके।

ईएसआई योजना की कवरेज सीमित है। इसमें वे सभी फैक्टरियां व संस्थान शामिल हैं, जहां कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हैं। छठे आर्थिक मतगणना 2013-14 के मुताबिक भारत में करीब 98 प्रतिशत प्रतिष्ठान 10 से कम कर्मचारी रखते हैं।

वैश्विक महामारी को लेकर किसने उठाए क्या कदम

- अमेरिका सहित कुछ देशों में बेरोजगारी बीमा के लाभ को विस्तार दिया गया है। फिलीपींस में 60,000 लोगों तक की नौकरियां जाने की स्थिति में बेरोजगारी लाभ देने की योजना तैयार की गई है
- जापान और इटली जैसे देशों ने वित्तीय सहायता और टेलीवर्किंग को अनुमति देने के लिए प्रक्रिया सरल की है
- आयरलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में भुगतान युक्त बीमारी की छुट्टी लेने का प्रावधान किया है
- फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में काम करने की अवधि में कमी, जिस पर वेतन कटौती नहीं होगी। आंशिक बेरोजगारी लाभ देते हुए उन घंटों के लिए भुगतान किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी ने काम नहीं किया है
- चीन सरकार ने नियोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे बीमार पड़ने वाले या संक्रमण रोकने के कदमों की वजह से विस्थापित कामगारों के कॉंट्रैक्ट रद्द न हों

स्रोत : आईएलओ

विवाद से विश्वास के नियम और फॉर्म अधिसूचित

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 19 मार्च

सरकार ने आखिरकार विवाद से विश्वास योजना के नियम अधिसूचित कर दिए, जिसका लाभ 13 दिन लिया जा सकता है। आयकर विभाग ने पोर्टल पर भी फॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत घोषणा करने की प्रक्रिया 5 चरणों वाली है, जिसके लिए 5 फॉर्म जारी किए गए हैं। बहरहाल विशेषज्ञों ने नियमों में विसंगति की ओर ध्यान दिलाया है कि कर देनदारी निर्धारित किए जाने के बाद कर भुगतान के लिए 30 दिन की समयसीमा दी गई है, जबकि अधिनियम में 15 दिन अवधि बताई गई है।

पात्र करदाता को फॉर्म 1 में अपनी घोषणा अधिकृत अधिकारी के पास प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कर बकाये, आकलन वर्ष, ऑर्डर का ब्योरा, पहले ही भुगतान की जा चुकी कर राशि आदि का ब्योरा मांगा गया है। इसके साथ ही छूट पाने के अधिकार की मांग या कोई राहत या कर बकाये से संबंधित किसी दावे के बारे में फॉर्म 2 में जानकारी देनी होगी। इसके बाद अधिकृत प्राधिकारी 15 दिन के भीतर फॉर्म 3 में आदेश देकर करदाता को भुगतान की जाने वाली राशि के निर्देश देगा। 30 दिन के भीतर फॉर्म 4 से करदाता संबंधित प्राधिकारी को भुगतान करेगा। आखिरकार फॉर्म 5 के तहत अधिकृत प्राधिकारी विवाद समाधान का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

रेल यात्रियों की आवाजाही पर फ्लू का असर

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 19 मार्च

चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे के लिए कोरोनावायरस रंग में भंग करने वाला साबित हो सकता है। इस साल मार्च महीने में मार्च 2019 की तुलना में आरक्षित यात्रियों व रेलवे की कमाई में क्रमश: 29 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की कमी आई है।

नैशनल ट्रांसपोर्टर ने इस सप्ताह 155 जोड़ी ट्रेनें रद्द की हैं। यह कोविड-19 के प्रसार पर काबू करने के लिए किया गया है। भारतीय रेल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 7 दिनों में यात्रियों की संख्या में 55 प्रतिशत और कमाई में 47 प्रतिशत कमी आई है।

इससे वित्त वर्ष 2019-20 की सालाना कमाई प्रभावित होगी, जिसमें पिछले साल की तुलना में वृद्धि दिखाई गई है। एक अप्रैल 2019 से 19 मार्च 2020 तक आरक्षित श्रेणी के यात्रियों (पीआरएस) की संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत बढ़कर 59.639 करोड़ हो गई है, जहबकि कमाई 5 प्रतिशत बढ़कर 35,623.1 करोड़ रुपये हुई है।

दिलचस्प है कि चालू वित्त वर्ष में (10 मार्च तक) पीआरएस और गैर पीआरएस सहित कुल यात्री कमाई करीब 50,161 करोड़ रुपये रही है, जो 2018-19 के पूरे साल के दौरान 51,057 करोड़ रुपये थी। यह उममीद की जा रही थी कि रेलवे पिछले साल हुई कमाई के आंकड़ों से बहुत आगे निकल जाएगा।

इस माह की शुरुआत में रेलवे से यात्रा पर असर नजर आना शुरू हुआ। 1 से 10 मार्च के बीच यात्रियों से कमाई 1,360 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की समान अवधि में हुई 1,442 करोड़ रुपये की तुलना में 6 प्रतिशत कम है। इसका मतलब यह है कि भले ही रेलवे पिछले साल के लक्ष्य को पार कर जाए, लेकिन वह 56,000 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए तय किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 61,000 करोड़ रुपये लक्ष्य रखा गया है।

फरवरी और मार्च महीने में स्वैच्छिक रूप से टिकट रद्द करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। बेंगलूरु की ऑनलाइन ट्रेन टिकट डिस्कवरी व बुकिंग इंजन कन्फर्मटिकट के सह संस्थापक दिनेश कोथा ने कहा, 'पिछले 2 सप्ताह के दौरान टिकट रद्द कराने वालों की संख्या बढ़ी है। पिछले 2 दिन मे कैंसिलेसन 37 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है।'

दिल्ली, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों को जाने वाली ट्रेनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। पटना-नई दिल्ली, मुंबई-नागपुर, मुंबई-पुणे, तिरुपति-सिकंदराबाद, अहमदाबाद-मुंबई, बेंगलूरु-चेन्नई, चंडीगढ़-नई दिल्ली और नई दिल्ली-वाराणसी मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नई बुकिंग में भी 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है।

उन्होंने कहा, 'फरवरी 2020 से कैंसिलेशन और बुकिंग में 20 प्रतिशत की कमी आई है।'

ऑनलाइन डेटा एनलिसिस और बुकिंग प्लेटफॉर्म रेलयात्री के आंकड़ों से भी पता चलता है कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल मार्च में टिकट रद्द करने वालों की संख्या 39 प्रतिशत बढ़ी है।

इसमें कहा गया है, 'फरवरी महीने में कुल 1,03,842 बुकिंग हुई, जिसमें से 42,732 बुकिंग कैंसिल की गई। इस हिसाब से कैंसिल किए जाने की दर 41 प्रतिशत है। वहीं पिछले साल इस महीने में कुल 1,10,732 बुकिंग हुई थी, जिनमें से 33,084 बुकिंग रद्द हुई और कैंसिल किए जाने की दर 30 प्रतिशत थी।'

इसके अलावा रेलवे ने 155 जोड़ी ट्रेनें रद्द की हैं, जिनमें 100 प्रतिशत रिफंड दिया जाता है। रेलवे ने लोगों को यात्रा से हतोत्साहित करने के लिए रेल यात्रियों को दी जाने वाली छूट रद्द कर दी है। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है।

रेलवे पर कोरोना का कहर

मार्च महीने में यात्रियों की संख्या में 22.81 प्रतिशत गिरावट, 155 जोड़ी रेलगाड़ियां रद्द

- 2018-19 की समान अवधि की तुलना में पिछले 7 दिन में आरक्षित यात्रियों की संख्या में 54.81 प्रतिशत गिरावट
- पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पिछले 7 दिन में यात्रियों से कमाई में 47.02 प्रतिशत की कमी
- वित्त वर्ष 2018-19 में रेलवे की 48,015 करोड़ रुपये कमाई की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 10 मार्च तक आरक्षित व गैर आरक्षित रेल यात्रियों से कमाई 4.47 प्रतिशत बढ़कर 50,160.57 करोड़ रुपये हो गई है

केंद्र ने अपने 50 फीसदी कर्मियों को घर से काम करने को कहा

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है और शेष कर्मचारी तीन समूहों में अलग-अलग अवधि के लिए रोजाना कार्यालय आएंगे। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में गुरुवार को इस सिलसिले में निर्देश जारी किए गए।

मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ग्रुप बी और सी के 50 फीसदी कर्मचारी रोजाना कार्यालय आएं, जबकि शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाए। आदेश में कहा गया, 'सभी विभागों के प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक रोस्टर बनाएं और उन्हें एक हफ्ते के अंतराल पर कार्यालय आने का निर्देश दें। हालांकि, पहले हफ्ते के रोस्टर पर फैसला करने के लिए विभागों के प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यालय के नजदीक रहने वाले या अपने वाहन से कार्यालय आने कर्मचारियों को शामिल करें।'

इसमें कहा गया है कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों का समय अलग-अलग होना चाहिए। आदेश में कहा गया, 'यह सलाह दी जाती है कि काम करने के घंटों के लिए कर्मचारियों के तीन समूह बनाए जाएं और उन्हें सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे का समय आवंटित किया जाए।'

इसमें कहा गया है, 'निर्धारित रोस्टर के मुताबिक किसी दिन घर से काम कर रहे अधिकारियों को टेलीफोन पर हर वक्त उपलब्ध रहना चाहिए। अत्यावश्यक स्थिति में उन्हें कार्यालय आना चाहिए।' मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्देश आवश्यक/ आपात सेवाओं में शामिल कार्यालयों और कर्मचारियों पर तथा कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के उपायों में सीधे तौर पर शामिल लोगों पर भी शामिल नहीं होंगे। *भाषा*

कोर्ट का यूपी को 2 हफ्ते वसूली रोकने के निर्देश

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 19 मार्च

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को वसूली कार्यवाही दो हफ्ते टालने के दिए निर्देश
- गोवा ने मूल्य वर्धित कर (वैट) रिटर्न्स मूल्यांकन को तीन महीने के लिए टाला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को कोरोनावायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी तरह की वसूली कार्यवाही को दो हफ्ते के लिए टालने का निर्दश दिया है। अदालत ने इसे छह अप्रैल तक रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि इस दौरान सभी नीलामी कार्यवाही लंबित रहेंगी।

अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी जानलेवा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसी तरह के आदेश दिए हैं। राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने भी इसी तरह के निर्णय लिए हैं।

उदाहरण के तौर पर गोवा ने 2016-17 के लिए मूल्य वर्धित कर रिटर्न्स के आकलन को तीन महीने के लिए टाल दिया है। इसके लिए 31 मार्च की निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। विशेषज्ञ चाहते हैं कि केंद्र सरकार को विभिन्न रिटर्न्स को दाखिल करने की समय सीमा में भी छूट देनी चाहिए।

केपीएमजी में कर पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा, 'सरकार आगे तीव्र रिफंड देने और स्थिति पर काबू करने के लिए सांविधिक फाइलिंग की अंतिम समय सीमा में छूट देने पर विचार कर सकती है।'

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेटों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस दौरान किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का निर्देश देने से रोक दिया है।

अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह विभिन्न अधिकारियों को जरूरी परिपत्र जारी कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाने को कहे जिसमें पीड़ित व्यक्ति को वैधानिक समाधान के लिए अदालतों में जाने पर मजबूर होना पड़े। महाराष्ट्र ने कर अधिकारियों को मूल्य वर्धित कर (वैट) परिपत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 2015-16 के लिए मूल्यांकन पूर्ण करने के लिए जरूरी सभी कागजात मेल के माध्यम से मंगाए जाएं ताकि अधिकारियों और संबंधित व्यक्ति के बीच न्यूनतम भौतिक संपर्क हो सके।

मप्र में आज साबित करना होगा बहुमत

बीएस संवाददाता,
भोपाल, 19 मार्च

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को विश्वास मत की प्रक्रिया पूरी करें। यह प्रक्रिया विधायकों के हाथ उठवा कर पूरी की जाएगी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और कांग्रेस के 16 बागी विधायक यदि सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहें तो उन्हें भोपाल लाया जाए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के डीजीपी को उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। उधर, प्रदेश के पूर्व मु यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। चौहान ने कहा कि सरकार अपना बहुमत गंवा चुकी है और कल उसका गिरना तय है।

उधर कांग्रेस नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीते पटवारी ने कहा कि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल करने को लेकर पूरी तरह आवश्स्त है। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा और सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इससे पहले बागी विधायकों को मनाने की आखिरी कोशिश में पूर्व मु यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें एक भावनात्मक पत्र लिखा और कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से विधायकों की बात करवा सकते हैं। मप्र विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं जिनमें दो विधायकों के निधन के बाद 228 सीटें बचीं। 22 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं जबकि भाजपा के पास कुल 107 विधायक हैं। चार विधायक निर्दलीय हैं जबकि सपा और बसपा के क्रमश एक और दो विधायक हैं।

बीएस सूडोकू 3693 | परिणाम संख्या 3692

5		6		2				
				1	3			
9		3			6			4
	4	8						2
1								6
7						5	3	
8			1			7		3
			9	7				
				5		8		9

9	1	6	2	7	3	5	4	8
3	7	4	8	5	6	2	1	9
2	5	8	1	4	9	3	7	6
7	9	3	6	1	2	8	5	4
5	6	1	4	3	8	9	2	7
8	4	2	7	9	5	1	6	3
1	8	7	3	2	4	6	9	5
4	3	9	5	6	1	7	8	2
6	2	5	9	8	7	4	3	1

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2030/2040, जौ 1825/1850, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2200, सरसों 3400/3500, तिल सफेद 8600/8800, सोया (टीन) 1440/1450, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1350/1400,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2040/2050, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3400/3450, स्टीम 3750/3800, लालमती 2900/2950, चावल (सोना) 2600/2650,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1345, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1425, फ्लेक 1365, डीएमओ 980, टरपीन लैस बोल्ड 1445

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1025/1080, खुरपा 960/985,चाकू 1030/1090, रसकट 940/945, शक्कर 1090/1100, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3250, सिहोरा 3120, बुंदकी 3130, बुढ़ाना 3180,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3450/3500, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1025, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 3950, खल: सरसों 2100/2200, बिनौला 2150/2250, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 4700/4800, गेहूं (मिल) 2090/2100, मक्की 1700/1750, बाजरा 1550/1600, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3250/3250, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4000/4025,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 1900/2000, ग्वार 3200/3250, जौ 1850/1900,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3400/3450, ग्वारगम 5300/5400, बाजरा (गुजरात) 1600/1650, बाजरा (जयपुर) 1600/1650, चना 4000/4150, काबली चना 4800/5000, मूंग 7200/7500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)94, राइसब्रान (अखाद्य) 91, खल सरसों 1950, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 850, लाल 850, कंटीन्यूअस 900,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 9000/9200, अरहर दाल 7400/8000, उड़द साबुत 7300/8200, उड़द धोया 8800/9400, छिलका 8300/8700, दाल मसूर 6200/6500, चनादाल 5100/5200,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5400/5500, सेला 4900/5000, शरबती साधारण सेला 3400/3500, शरबती स्टीम 3900/4000,चावल 1509 सेला 4450/4500, धान: शरबती 1950/2000,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3890/3950, हरियाणा 3880/3900, राजस्थान 3880/3930, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2250/2350, सरसों खल 1990/2000,

फाजिल्का
(जीएसटी अतिरिक्त): धान (1509) 2400/2450, धान मोटा 1550/1575, चावल कच्चा (आईआर-8)2200/2300, चावल सेला (आईआर-8) 2200/2250, चावल कच्चा (पीआर-11) 2700/2800,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2060/2080, चावल परमल कच्चा 2300/2325, से ला 2225/2260, मक्की यूपी 1750/1775, दाल उड़द छिलका 8800/10000, चना देशी 4800/4900, दाल चना 5150/5250, काबली चना 5100/6300, राजमां चित्रा पुणे 7600/8600,चीन 8700/8800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2050/2060, बासमती चावल 5500/5550, धान 1121 नं. 2650/2725, पूसा 1509 धान 2300/2400, शरबती धान 1900/1925, सेला (1509 नं.) चावल 4250/4350, स्टीम 5400/5500,

हिसार
ग्वार 3200/3250, जौ 1840/1850, सरसों 3550/3700, मूंग 7000/7100, गेहूं 2040/2050,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 975/1000, मैदा 1100/1110, देशी घी (एक ली/जार) 308/470, रिफाइंड (टीन) 1310/1350,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3750/3800, खल बिनौला मोटी 2100/2300, बिनौला 2500/3100, सरसों तेल 8150/8200, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3150/3200, बाजरा 1575/1600 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 28

निजी क्षेत्र की मदद

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त हमारे देश के लिए किसी महामारी के प्रबंधन में परीक्षण की गति तेज करना अहम है। अब तक देश में नोवल कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। परंतु दिक्कत यह है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि परीक्षण की सुविधा सीमित है। ऐसा तब है जबकि सरकार बार-बार दोहराती रही है कि उसके पास जांच करने वाले किट का भंडार मौजूद है। यदि ऐसा है तो परीक्षण की गति तेज की जानी चाहिए। बहुत संभव है कि अधिकारी इस जांच किट को बचाकर रखना चाहते हों ताकि वायरस के व्यापक समुदाय में फैलने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि जो लोग विदेश यात्राओं पर नहीं गए उनमें या पुराने कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आए लोगों में इस बीमारी के प्रसार को सामुदायिक प्रसार कहा जा सकता है। यह नीति सही नहीं है। बल्कि जैसा कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों में देखा गया, शुरुआत में ही व्यापक जांच होने पर बेहतर नतीजे हासिल हुए।

जांच किट के व्यापक इस्तेमाल के लिए उसका सस्ता होना, व्यापक उपलब्धता और उत्पादन करना आवश्यक है। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रक्रिया में शामिल करना होगा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकारी क्षेत्र जरूरत के मुताबिक किट तैयार कर पाएगा। ऐसी खबरें आई हैं जिनके मुताबिक जो निजी कंपनियां जांच किट के उत्पादन में मदद करना चाहती हैं उन्हें जरूरी मंजूरी मिलने में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं। कम से कम इस वक्त ऐसी बाधा सामने नहीं आनी चाहिए। कारोबारी सुगमता को लेकर भारत का स्वाभाविक दिक्कतदेह रुख ऐसे राष्ट्रीय और मानवीय महत्त्व के मुद्दों पर आड़े नहीं आना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कई कंपनियों को अपने जांच किट के प्रमाणन के लिए यहां वहां दौड़ लगानी पड़ रही है। केवल राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) को यह मंजूरी प्रदान करने की क्षमता हासिल है। इस वक्त उस पर भी बहुत अधिक दबाव है। स्वास्थ्य अधिकारियों को सबसे पहले ऐसे वैकल्पिक स्रोत तैयार करने चाहिए जो इन जांच किट को प्रमाणित कर सकें ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके। यदि जरूरत पड़े तो सरकार को उचित मूल्य पर इनकी थोक खरीद भी करनी चाहिए या निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को इनकी सब्सिडी आधारित खरीद मुहैया करानी चाहिए ताकि लोग इच्छा होने पर जांच करा सकें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का सुझाव है कि इस वायरस की नि:शुल्क जांच की जाए लेकिन ऐसी स्थिति में यदि सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो निजी क्षेत्र मदद के लिए आगे नहीं आएगा।

इतना ही नहीं इस देरी से सबक लिया जाना चाहिए और महामारी से निपटने की तैयारी के अन्य पहलुओं में इससे बचा जाना चाहिए। भारत में गहन चिकित्सा तैयारी की काफी कमी है। इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। फिलहाल औसतन एक लाख भारतीयों पर 2.3 गहन चिकित्सा बेड उपलब्ध हैं। यह आंकड़ा शेष विश्व से काफी कम है। जाहिर सी बात है कि ऐसी तैयारी और पृथक्करण क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ तालमेल से कम समय में मुहैया कराया जा सकता है5। सरकार को उच्चतम स्तर से इस प्रक्रिया का नियंत्रण संभालना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे गतिरोध सामने नहीं आएं, जैसे जांच किट के उत्पादन में देखने को मिले। भारत को कोविड-19 का खतरा कम करने के लिए अधिकाधिक जांच सुविधाओं की आवश्यकता है। अब तक सरकार ने बचाव के उपाय अपनाने में अच्छा काम किया है। अब वक्त आ गया है कि इसके अगले चरण में प्रवेश किया जाए।

अजय मोहंती

कोरोनावायरस और बाजार की मार

दुनिया भर में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण से अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ती दिख रही है। इसके तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं **आकाश प्रकाश**

वित्तीय बाजारों के लिए यह महीना कितना खराब रहा है? हमने हाल ही में वैश्विक इक्विटी बाजार को अब तक की सबसे बड़ी गिरावट से जूझते देखा है। महज कुछ हफ्तों में ही अमेरिकी प्रतिभूतियों में सबसे बड़ी उछाल और तेल कीमतों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। डर और उठापटक का माहौल फैलता जा रहा है। वित्तीय बाजार अव्यवस्थित हो चुके हैं। बाजार पर डर के असर को परखने वाला वीआईएक्स सूचकांक वर्ष 2008 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है।

शुरुआती दौर में एक क्षेत्रीय संकट के तौर पर देखी जा रही यह आपदा वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। पश्चिमी जगत के अधिक उन्नत देश कोविड-19 वायरस की मार कहीं ज्यादा झेल रहे हैं। वे बेपरवाह और असावधान होने के साथ ही इससे निपटने के लिए तैयार भी नहीं थे और अब इसके संक्रमण पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां चीन ने इस घातक वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों को बंद करने की गंभीर आर्थिक पीड़ा उठाने से गुरेज नहीं किया, वहीं पश्चिमी देशों ने आसान विकल्प आजमाए। उनकी चिंता वित्तीय प्रणाली और इक्विटी बाजारों को बचाए रखने को लेकर कहीं अधिक दिखी। यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका ने कोविड-19 का फैलाव होता देख शुरुआती दौर में ब्याज दर की कटौती और तरलता समर्थन पर ध्यान दिया जबकि इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान एवं उन्हें अलग-थलग रखकर इलाज करने पर ध्यान देना चाहिए था। अमेरिकी प्रतिक्रिया का नेतृत्व फेडरल रिजर्व कर रहा था, न कि बीमारी नियंत्रण केंद्र (सीडीसी)।

चीन इस बीमारी के नए संक्रमणों पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रहा है। उसने वायरस के मुख्य केंद्र हुबेई प्रांत और कुछ अन्य इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया। सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया सघन जांच, संदिग्धों को अलग रखने और उनके इलाज के जरिये इस वायरस का प्रसार रोकने में कामयाब रहे हैं।

वायरस का प्रसार इटली तक होने और बहुत तेजी से संक्रमण फैलने के बाद यह साफ हो गया कि यूरोप के पास ऐसे सामाजिक ढांचे, कानून, संस्थागत क्षमता या संसाधन नहीं हैं कि वह सिंगापुर या दक्षिण कोरिया में सफलतापूर्वक आजमाए जा चुके तरीकों को लागू कर सके। इटली और बाकी यूरोपीय देशों के पास अब चीन जैसा सख्त कदम उठाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है। उन्हें भी देश के बड़े हिस्सों को बाहरी संपर्क से पूरी तरह अलग रखना और एक जगह लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाना होगा। ऐसा नहीं होने पर उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली धराशायी हो जाएगी। अमेरिका को भी 10-15 दिन बाद यही कदम उठाने होंगे। वैसे चीन में यह देखा जा चुका है कि किसी शहर या इलाके को पूरी तरह बंद करने की आर्थिक लागत काफी भयावह होगी। चीन में नए मामले काफी कम हो जाने के बावजूद वहां के अधिकांश कारखाने अभी तक अपनी पुरानी क्षमता के 65 फीसदी स्तर तक ही पहुंच पाए हैं। अनुमान है कि 2020 की पहली तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेगी। लेकिन इतनी बड़ी आर्थिक लागत के बावजूद इस वायरस के तीव्र संक्रमण एवं 1-3 फीसदी मृत्यु दर को देखते हुए इस पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाना सामाजिक स्तर पर अस्वीकार्य है। इंसानी जिंदगी के संदर्भ में भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, अगर सभी सामाजिक संपर्कों पर रोक लगाने के कदम फौरन नहीं उठाए जाते हैं।

अब यह अपरिहार्य ही है कि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चली जाएगी। बहस केवल इस बात पर है कि क्या यह दो तिमाहियों तक रहने वाली एक तकनीकी घटना है या फिर इससे कहीं अधिक लंबी और गहरी होगी।

किसी आम मंदी में कंपनियों की आय गिरती है और बाजार 25-30 फीसदी तक लुढ़क जाते हैं। लेकिन कोरोना के चलते पैदा होने वाली मंदी के आम मंदी जैसा रहने की संभावना नहीं है क्योंकि इस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अचानक विराम लगा है। खपत लुप्त होने और आपूर्ति शृंखलाओं के ध्वस्त होने से कई क्षेत्र गहरे आघात का सामना करने वाले हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ऐसा कब तक जारी रहेगा? वैश्विक वित्तीय संकट के उलट इस संकट का समाधान केंद्रीय बैंक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकारों से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पूरी संभावना है कि संकट खत्म होने के पहले एयरलाइन, आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योगों को बेलआउट पैकेज दिए जाएंगे।

बाजारों में खासा डर देखा जा रहा है क्योंकि कोरोना के चलते दुनिया भर के उच्च-प्रतिफल वाले बाजारों को तगड़ा आघात लगने के आसार हैं। विश्वव्यापी मंदी छाने और तेल कीमतों में तीव्र गिरावट के बीच उच्च-प्रतिफल बाजारों का बड़ा हिस्सा मुश्किल में है क्योंकि नकदी प्रवाह की समस्या है। ऋण विस्तार बढ़ा है लेकिन वर्ष 2008 के स्तरों तक पहुंचने के पहले अभी लंबा सफर तय करना होगा। नए कर्ज बंद होते ही कर्ज चुका पाने में सक्षम कई कंपनियों को भी परिपक्वता जोखिम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे परिपक्व होने वाले बॉन्ड का भुगतान नहीं कर पाएंगी। कम-से-कम एक लाख करोड़ डॉलर के बीबीबी कागजात हैं जिन्हें डाउनग्रेड किए जाने और अ-निवेश श्रेणी के स्तर पर लुढ़कने की आशंका है। यह उच्च-प्रतिफल परिसंपत्ति समूह के आकार के दोगुने से अधिक होगा और इससे प्रतिफल बढ़ेगा क्योंकि इन बॉन्ड को खरीदने के लिए समुचित ग्राहक ही नहीं हैं। हम उच्च-प्रतिफल वाले कई फंड एवं ईटीएफ पर इस शोधन का असर पड़ते हुए भी देख रहे हैं। ये ऋणशोधन चोट पहुंचा रहे हैं क्योंकि बैंकों ने अपने बाजार-निर्माण में कमी की है जिससे तरलता की कमी और कीमतों में गड़बड़ी पैदा हुई है। बेहद कम प्रतिफल को देखते हुए मार्जिन जुटाने के लिए निवेशक आधार के बीच लाभ उठाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालत यह हो गई है कि 50 लाख से 1 करोड़ डॉलर तक के छोटे कारोबार कर पाना भी मुश्किल लग रहा है। हमें करीबी नजर रखनी होगी कि यहां क्या होता है और उसका संभावित संक्रमण कैसा रहता है? यह आसन्न खतरे की चेतावनी हो सकती है।

नीति-निर्माताओं ने अब पैनिक बटन दबा दिया है। फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है और राहत पैकेज अगला कदम है। छोटी एवं मझोली कंपनियों, कंपनियों और अन्य तनावग्रस्त क्षेत्रों में तरलता बनाए रखने और ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के कदम वैश्विक स्तर पर उठाए जा सकते हैं।

हम कोरोना संकट से बाहर निकलेंगे और बाजार एवं अर्थव्यवस्था दोनों ही सामान्य हो जाएंगी। लेकिन इसमें किसी व्यक्ति को धीरे-धीरे और सोचे-समझे ढंग से खरीद करनी चाहिए। इटली में सामने आने वाले नए मामलों पर नजर रखनी होगी। जैसे ही यह साफ हो जाता है कि इटली कोरोना के प्रसार पर काबू पाने लगा है और हालात नियंत्रण में आने लगे हैं, बाजार को यह लगने लगेगा कि पश्चिम के दूसरे देश भी इस राह पर चल सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो अगर हम गर्मी एवं नमी के चलते कहीं बेहतर प्रतिरोधक क्षमता होने और सीमाओं को बंद करने से इस वायरस को काबू में रख पाते हैं तो यह खरीदारी का मौका लेकर आएगा। तेल कीमतों में आई गिरावट और वैश्विक तरलता बढ़ने एवं ब्याज दरों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर होने से भारत को लाभ होगा। हम एक साल से अधिक समय से सुस्ती के दौर में हैं और वैश्विक आपूर्ति शृंखला से बाकी देशों जैसा नजदीकी जुड़ाव भी नहीं है। दुनिया के उभरते बाजारों में भारी शोधन का असर भारत पर भी बराबर पड़ा था क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा निष्क्रिय प्रवाह का है। भारत के कुछ जोखिमों पर आखिरकार ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी क्षेत्र की साफ-सफाई का काम काफी हद तक पूरा होने के करीब है। मूल्यांकन कहीं अधिक संवेदनशील दायरे में है। अगर भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो फिर समस्या होगी। अन्यथा यह भारतीय निवेशकों के लिए खरीद का मौका लाएगा और लंबे समय तक तेजी का रुख रहेगा।

बैंकों को उबारने की नीति पर विचार करने की जरूरत

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

येस बैंक संकट से कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हो गए हैं, जिन्हें अब कोई नहीं पूछ रहा है। ये सभी प्रश्न 21वीं शताब्दी के लिहाज से महत्त्वपूर्ण हैं और बैंकों के पतन, इससे निपटने के उपाय और जिन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, उनसे संबंधित हैं। मेरे विचार से इन प्रश्नों का जवाब खोजना अहम है। पिछली शताब्दी के दूसरे हिस्से से हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि करदाताओं को बैंकों को रसातल में जाने से बचाना चाहिए। इससे ऐसी धारणा को बल मिला है कि बैंक घरों की तरह ही सुरक्षित हैं। हालांकि ऐसी सोच क्यों है कि बैंक जोखिम मुक्त हैं और लोग जितनी चाहे उतनी रकम इनमें रख सकते हैं। क्या केवल इसलिए कि बैंक जमाकर्ताओं को उनकी रकम पर ब्याज देते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि यह झूठी अवधारणा किसने आगे बढ़ाई है? यह कब और किस उद्देश्य से आई?

यह सोचना बिल्कुल बचकाना होगा कि किसी वित्तीय लेनदेन में जोखिम नहीं होता है। जोखिम तो हमेशा बना रहता है। यह तब भी होता है जब आप बैंक में रकम डालते हैं और इस पर सरकार की पूरी गारंटी मिली होती है। लिहाजा, जब किसी बैंक का कारोबार किसी भी वजह से ठप होता है तो कम से कम तीन प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए। क्या 'सावधान ग्राहक' जैसी वैधानिक चेतावनी जमाकर्ताओं के मामले में भी लागू होती है? किसी अन्य कारोबार की तुलना में बैंकों की अधिक जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए? अगर वित्तीय उत्तरदायित्व के लिए धन करदाताओं को देना है तो यह कितना उचित है?

इस संदर्भ में एक उदाहरण पर विचार किया जा सकता है। म्युचुअल फंड कंपनियां अपने ग्राहकों को बाजार जोखिमों के बारे में बताती हैं और इसके लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। यह भी सच है कि यह औपचारिकता से अधिक नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बैंकों के लिए भी ऐसी चेतावनी क्यों जारी नहीं होती है? मेरा मानना है कि न केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को नियमित रूप में इस बारे में विज्ञापन देना चाहिए बल्कि प्रत्येक बैंक को अपनी चेकबुक पर यह चेतावनी छापनी चाहिए। अंशधारकों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों को भी बैंकों से जुड़े जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। मैं मजाकिया लहजे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं। मामला कुल मिलाकर सिगरेट की तरह ही है और आने वाले समय में हालात और बदतर होंगे। अब यह माना जाने लगा है कि बैंकों को दूसरे कारोबारों के मुकाबले अधिक उत्तरदायित्व के साथ काम करना चाहिए। लेकिन यह कितना विरोधाभासी कथन है। अनिश्चितता के कारण एक जवाबदेह बैंक का ऋण खाता (लोन बुक) शून्य होगा।

नियम कायदे एवं अनुपालन अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन तकनीकी बातों का भी ध्यान रखना होगा। इन चीजों से आपको यह मालूम नहीं होगा कि उधार लेने वाला व्यक्ति गैर-जिम्मेदार है या चीन एक बार फिर वुहान जैसे हालात दुनिया पर थोपने वाला है। अनिश्चितताएं कुछ ऐसी ही होती हैं। जब जोखिम अधिक होता है तो बैंक अधिक ब्याज वसूलते हैं, लेकिन ऊंची जमा दर के संदर्भ में देखें तो बैंक अपने ग्राहकों को संकेत देते हैं कि वे अधिक जोखिम ले रहे हैं।

तीसरी अहम बात यह है कि अगर ढांचागत वित्तीय स्थिरता पर किसी एक बैंक के पतन का असर होता है तो करदाताओं, जो किसी अनुबंध का हिस्सा नहीं हैं, को क्यों अंशधारकों को बचाना चाहिए? कुल मिलाकर बात नैतिक जोखिम के इर्द-गिर्द ही घूमने लगती है। इसका आशय एक ऐसी स्थिति से है, जिसमें कोई बीमित व्यक्ति अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस जोखिम के लिए भुगतान किसी दूसरे को करना होता है। यह परंपरागत चेतावनी को भी धता बता देता है। हालांकि इसके बाद भी हम बैंकों को उबारने का जिम्मा करधारकों के माथे पर डाल देते हैं।

वर्ष 1907 में जे पी मॉर्गन ने इस मान्यता को बढ़ावा दिया कि बैंक खास संस्थान होते हैं, इसलिए उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने आपात परिस्थितियों के लिए एक 'संकट मोचक' बैंक का प्रस्ताव दिया और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गठन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फेडरल रिजर्व की स्थापना मुख्य रूप से अमेरिकी बैंकों के अंशधारकों को बचाने के लिए की गई थी। मॉर्गन ने सोचा कि बैंक के जमाकर्ता जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन अंशधारक कोई जोखिम नहीं ले सकते हैं।

दूसरी तरफ यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) का गठन मुद्राएं छापने और सरकार को उधारी देने के लिए किया गया था। इन पर अक्सर निजी नियंत्रण रहा। इनमें बैंक ऑफ इंगलैंड (बीओई) दूसरा सबसे पुराना बैंक था, जिस पर 1946 तक निजी नियंत्रण था, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक भी 1949 तक निजी नियंत्रण में था। कुछ देशों में वे अब निजी नियंत्रण में हैं। 1970 तक दो तरह के बैंक थे। इनमें एक वे थे, जिन्होंने सरकार को बचाया था और दूसरे वे थे, जिन्होंने अन्य बैंकों को डूबने से बचाया था। तब से वे दोनों को ही बचाते आ रहे हैं और करदाता इसका भुगतान करते हैं।

हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जमाकर्ता भी करदाता ही होते हैं। एक जमाकर्ता भी कर भुगतान करता है। एक जमाकर्ता के रूप में वह जो भी अर्जित करता है उसे करदाता के रूप में इसे खोना पड़ सकता है। बैंकों को किसी भी सूरत में बचाने का चलन राजनीतिक दबाव में और अधिक विकृत हो गया है। लोगों के मन में यह बात डाल दी गई है कि बैंकों को नहीं बचाने से पूरे आर्थिक ताने-बाने पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सरकार को उसी समय हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए जब चीजें बिगड़ जाती हैं? यही वजह है कि मुझे लगता है कि बैंकों को उबारने की पूरी नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जब सरकार के पास रकम रहती है तब तक यह कवायद चल सकती है, लेकिन आर्थिक मंदी मंडराने के समय में क्या उसके पास ऐसी क्षमता होगी?

कानाफूसी

निष्कासन में षडयंत्र

करीब दो दशक तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और इस दौरान केंद्र सरकार में मंत्री पद तक संभाल चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ले ली। बदले में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के कई निष्कासित कांग्रेसियों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से गुजारिश की है कि अनुशासनहीनता के लिए किया गया सिंधिया का निष्कासन खत्म किया जाए। कांग्रेस अनुशासन समति को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वह वर्षों से पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं और उनका निष्कासन पार्टी संविधान के खिलाफ है। उन्होंने मामले की आंतरिक जांच की मांग करते हुए लिखा है कि दोषियों को दंडित किया जाए। इन पुराने कांग्रेसियों ने अपने निष्कासन में गहरे षडयंत्र की भी आशंका जताई है।

पत्राचार या जंग

ई-मेल के इस युग में मध्य प्रदेश में संवैधानिक पदों पर आसीन दो लोग- मुख्यमंत्री कमल नाथ और राज्यपाल लालजी टंडन, संभवत: पत्र लेखन की लुप्तप्राय विधा को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे को कई पत्र लिखे हैं। इतने कि अब लोग इसे 'पत्र युद्ध' की संज्ञा देने लगे हैं। सबसे पहले टंडन ने कमल नाथ को पत्र लिखकर कहा कि वह सदन में अपना बहुमत साबित करें और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी सरकार को अल्पमत का मान लिया जाएगा। इसके बाद नाथ ने उत्तर दिया कि वह राज्यपाल का पत्र अग्रिम कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित कर रहे हैं ताकि वह उस पर 'उचित कदम' उठा सकें। नाथ ने पत्र की एक प्रति विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति को भी भेज दी। इसके बाद भी दोनों के बीच पत्राचार का सिलसिला जारी रहा।

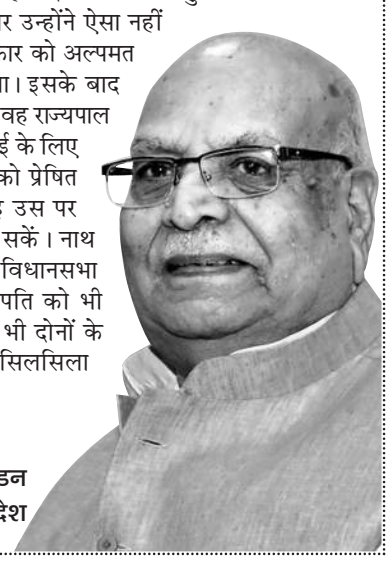

लालजी टंडन
राज्यपाल, मध्य प्रदेश

आपका पक्ष

कुदरत का प्रकोप तो नहीं कोरोनावायरस?

कोरोनावायरस ने सारी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। दुनिया के बड़े-बड़े देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस दुनिया में ज्यादा तबाही न मचाए, इसके लिए हर देश भरपूर कोशिश कर रहा है। हमारे देश में भी कई मामले सामने आ चुके हैं जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल देश में इस वायरस से पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार, प्रशासन और अन्य कई संस्थाएं कोरोनावायरस के प्रति सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। आम लोग भी इससे बचने के उपाय कर रहे हैं। कोरोनावायरस ने दुनिया में महामारी का खतरा बनकर यह समझा दिया है कि विज्ञान के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे करने वाला इंसान अब भी कुदरत के आगे बौना है इसलिए अगर दुनिया को भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों से बचना है तो सबसे पहले सभी देशों के

यह वायरस दुनिया में ज्यादा तबाही न मचाए, इसके लिए हर देश भरपूर कोशिश कर रहा है

नागरिकों को अपने खानपान और जीवनशैली पर ध्यान देना होगा। इससे पहले भी चीन में फैली जानलेवा महामारियों का कारण जंगली जानवर, पशु-पक्षी ही थे। चीन से अस्तित्व में आए इस कोरोनावायरस की वजह भी वहां के लोगों द्वारा प्रदूषित जीव-जंतुओं का सेवन ही बताया गया है। हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति भी है, उन्हें आगे लाकर लोगों को कोरोनावायरस से बचाव के उपाय बताने चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोरोना के लक्षण महसूस होते हैं, तो उसे देसी और घरेलू इलाज छोड़कर अस्पताल जाना चाहिए। इंसान हर क्षेत्र में चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन शुद्ध आबोहवा के बिना खुशहाल रहकर स्वस्थ नहीं रह सकता है। धन-दौलत से इंसान महंगा इलाज तो करा सकता है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। इंसान आधुनिकता और भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में इस कदर दौड़ रहा है कि उसे अपने वातावरण का भी ख्याल नहीं रहा। वातावरण के प्रति लापरवाही जीव-जंतुओं के बाद अब खुद इंसान की जान पर भी भारी पड़ने लगी है। अब भी मौका है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाएं। कुदरत को संभालने और बढ़ते प्रदूषण के संबंध में सरकारों और आमजन को बिना किसी स्वार्थ के एकजुट होकर प्राथमिक और युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

गैर-जरूरी वस्तुओं का बंद हो आयात

आज हमारे देश में गैर-जरूरी वस्तुओं का आयात काफी बढ़ चुका है। यहां गैर-जरूरी वस्तुओं का मतलब उन वस्तुओं से है जो देश के घरेलू उद्योग में तैयार होती हैं। इन आयातित वस्तुओं की वजह से उद्योगों और रोजगार को बचाना चुनौती बना हुआ है। कई उद्योग ऐसे हैं जिनका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से होता है तथा इनसे ग्रामीण रोजगार उत्पन्न होता है। एक सवाल यह भी उठता है कि घरेलू उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं आयातित वस्तुओं से मुकाबला क्यों नहीं कर पाती हैं? दरअसल इसकी मुख्य वजह यह है कि आयातित वस्तुओं की कीमत कम रहती है और इनमें बहुत विविधता भी होती है। इसलिए सरकार को ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही इन उद्योगों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता और विविधता पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।

विमलेंद्र मणि त्रिपाठी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

बिकवाली से धातुओं में गिरावट

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 19 मार्च

कई क्षेत्रों और देशों में कोरोनावायरस के नए मरीज सामने आने के बाद पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता की वजह से बिकवाली दबाव बरकरार है। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर धातु कीमतों में तीन से छह प्रतिशत के बीच गिरावट दर्ज की गई।

औद्योगिक धातुओं के भाव गुरुवार को कमजोरी के साथ खुले और यूरोपीय संघ द्वारा अर्थव्यवस्था को संभावित संकट से बचाने के लिए ताजा मौद्रिक सहायता दिए जाने की खबरों के बाद दोपहर को कुछ सुधार देखने को मिला। लगातार बिकवाली दबाव, मार्जिन कॉल और मुनाफावसूली से एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में औद्योगिक धातुओं की कीमतें नीचे आ गई थीं।

जहां 31 मार्च, 2020 की डिलिवरी वाला तांबा वायदा 6 प्रतिशत तक गिरकर कई वर्षों के निचले स्तर 360 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, वहीं सीसे और जस्ते के अनुबंधों में भी 3 और 5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर गुरुवार को सुबह के कारोबार में धातुएं 8 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 4,400 डॉलर प्रति टन पर थीं, क्योंकि इनमें भारी बिकवाली देखी गई थी। शांघाई मेटल एक्सचेंज पर तांबा कीमतें 9 प्रतिशत तक नीचे आईं। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों ने कोरोनावायरस को लेकर बढ़ते जा रहे भय की वजह से अपने पोजीशन निपटाए। धातुओं में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई जिनमें कई धातुएं अक्टूबर 2008 यानी लीमन ब्रदर्स संकट के बाद से सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुईं।

आनंद राठी ऐंड स्टॉकब्रोकर्स के निदेशक (जिंस एवं मुद्रा) नवीन माथुर ने कहा, 'एमसीएक्स पर धातुओं के भाव में एलएमई पर कीमतों के अनुरूप बदलाव देखा गया। इसके अलावा, औद्योगिक धातुओं पर आज इक्विटी बाजारों के रुझान का असर दिखा। कमजोर शुरुआत के बाद प्रमुख धातुएं भी इक्विटी बाजारों में सुधार के बाद गुरुवार के कारोबार के मध्य में मजबूत हुईं। हालांकि कुल मिलाकर, कोरोनावायरस के तेज प्रसार की वजह से धातुओं में धारणा कमजोर बनी हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है।'

इस बीच, मार्च डिलिवरी के लिए कच्चा तेल वायदा 4.14 प्रतिशत तक की तेजी के साथ 1,686 रुपये प्रति बैरल पर पहुंचा।

दोपहर के कारोबार में मार्च डिलिवरी के सोना और चांदी वायदा भी 0.5 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ 39,702 रुपये प्रति 10 ग्राम और 34,435 रुपये प्रति किलोग्राम पर थे।

जवेरी बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ 40,334 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी कुछ नरम पड़कर बुधवार के 35,515 रुपये की तुलना में गुरुवार को 35,200 रुपये पर बंद हुई।

इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून!

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 19 मार्च

पूर्वानुमान

- बारिश में 'अल नीनो' तटस्थ रहने के आसार
- अप्रैल के उत्तरार्द्ध में मिल पाएगी पूर्वानुमान की विस्तृत जानकारी

निराशाजनक खबरों के बीच मौसम के संबंध में कुछ अच्छी खबर है। मौसम के नवीनतम पूर्वानुमान से पता चलता है कि मॉनसून से पहले के महीनों के दौरान तथा देश में मॉनसून की शुरुआत होने के बाद भी यानी मई, जून और जुलाई महीने में खौफनाक अल नीनो 'तटस्थ' रहने के आसार हैं। एल नीनो मौसम की वह दशा है जिसे भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की गति बाधित करने वाला माना जाता है।

मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान बताता है कि इसके बाद समुद्र की सतह के तापमान में और गिरावट आ सकती है जिससे जुलाई के बाद ला नीना की संभावना जोर पकड़ सकती है। मौसम के इन हालातों से संकेत मिलता है कि इस बार भारत में मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जून के महीने में भारत में प्रवेश करता है और सितंबर के बाद से वापस जाना शुरू कर देता है। मॉनसून के मौसम के लिए जुलाई सबसे महत्त्वपूर्ण महीना होता है क्योंकि इस महीने में बारिश की मात्रा अधिकतम होती है। देश की कृषि और सामान्य अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा मॉनसून महत्त्वपूर्ण रहता है क्योंकि देश के आधे से भी कम खेतों में सिंचाई की जाती है। अल नीनो को पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान (एसएसटी) में दीर्घ अवधि के औसत से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि इसके उलट ला नीना को उसी क्षेत्र पर एसएसटी में दीर्घ अवधि के औसत से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है।

भारत के दक्षिण-पश्चिम मॉनसूनी मौसम के प्रदर्शन में अल नीनो बड़ी भूमिका निभाता है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट द्वारा अध्ययन किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 135 वर्षों के दौरान 1880 से 2014 तक अल नीनो वाले लगभग 90 प्रतिशत वर्षों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 65 प्रतिशत वर्षों में अल नीनो विकसित होने से सूखा पड़ा है।

स्काईमेट ने रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अल नीनो वर्ष के दौरान आम तौर पर औसत से कम बारिश होती है जिससे फसल उत्पादन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) भी ऐसा कारक है जो भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के प्रदर्शन पर असर डालता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि के दौरान यह भी तटस्थ रहने की उम्मीद है।

इस सबसे यह उम्मीद जोर पकड़ती है कि अगर हालात में कोई बड़ा उलट-फेर नहीं होता है, तो शुरुआती संकेतों के अनुमसार वर्ष 2020 में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य रह सकता है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जहां तक वर्ष 2020 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का संबंध है, तो अब तक हमें कोई भी बड़ी प्रतिकूल स्थिति नजर नहीं आई। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद यह स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी।

आलू-प्याज की मांग बढ़ी, कीमतों में तेजी

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 19 मार्च

दिल्ली मंडी

- बाजार बंद होने की चर्चाओं से दिल्ली की मंडियों में बढ़ी आलू और प्याज की मांग
- मंडियां बंद होने के डर से खुदरा कारोबारी ज्यादा खरीद रहे आलू-प्याज
- फिलहाल किल्लत नहीं, आने वाली आवक की हो रही पूरी बिक्री

कोरोनावायरस से मंडी बंद होने की आशंका के कारण दिल्ली में आलू-प्याज की मांग बढ़ गई है जिससे इनकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इस सप्ताह दिल्ली की मंडियों में आलू-प्याज के दाम 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। पिछले सप्ताह तक मंडियों में आने वाले प्याज-आलू की आवक का एक बडा हिस्सा बिना बिके रह जाता था, लेकिन दो-तीन दिन से करीब-करीब सारा माल बिक रहा है। कारोबारी और मंडी प्रशासन मंडियों के बंद होने की बात को अफवाह बता रहे हैं।

दिल्ली की आजादपुर मंडी स्थित पोटैटो ऐंड अनियन मर्चेंट एसोसिएशन (पोमा) के अध्यक्ष और आलू कारोबारी त्रिलोकचंद शर्मा कहते हैं कि कोरोनावायरस के कारण मंडियों के बंद होने की अफवाह से मंडी में आलू की मांग बढ़ी है जिससे इनके भाव में भी इजाफा हुआ है। शर्मा कहते हैं कि मंडी में आलू की कमी नहीं है। लेकिन मांग बढ़ने से दाम तेज हुए हैं। पहले मंडी में आने वाली आलू की गाड़ियों में से काफी गाड़ी बिना बिके रह जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। बुधवार को कुल 190 गाड़ी आलू की उपलब्धता थी। इसमें से तीन गाड़ी छोडकर बाकी पूरा आलू बिक गया। गुरुवार को आलू की आवक 130 गाड़ी रही। देर शाम तक इनके भी बिकने की संभावना है। शर्मा ने कहा कि आलू की मांग बढ़ने से बीते दो दिन में आलू का थोक भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ चुका है।

आजादपुर मंडी के पूर्व अध्यक्ष और प्याज कारोबारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि खुदरा कारोबारी पहले के मुकाबले ज्यादा प्याज खरीद रहे हैं। इससे बीते दो-तीन दिन में प्याज के थोक भाव 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ चुके हैं। मांग को देखते हुए किसानों से ज्यादा प्याज लाने को कहा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि लंबी दूरी से प्याज लाने वाले कोरोना के डर से इसकी ढुलाई से बच रहे हैं। अगर अगले कुछ दिनों में ऐसा होता है तो प्याज की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हालांकि गुरुवार को 10 गाड़ी ज्यादा प्याज आया है। दिल्ली के लिए राहत की बात यह भी है कि राजस्थान से प्याज की नई आवक शुरू हो चुकी है। लेकिन कोरोना के भय से कीमतों में अनिश्चितता रह सकती है। फिलहाल बाजार में तेजी दिख रही है। आजादपुर मंडी में आलू के दाम 800 से 1,550 रुपये से बढकर 1,000 से 1,850 रुपये और प्याज के दाम 1,200 से 2,000 रुपये से बढकर 1,500 से 2,500 रुपये हो चुके हैं।

कोरोनावायरस से विमानन और परिवहन क्षेत्र प्रभावित

कोरोनावायरस महामारी के कारण विमानन कंपनियों की उड़ानें रद्द होने और औद्योगिक गतिविधियों में कमी की वजह से मार्च के पहले दो सप्ताह में ईंधन की मांग 10 से 11 प्रतिशत घटी है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने एक बयान में कहा कि पेट्रोलियम उद्योग सभी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर कोरोना वायरस के प्रभाव पर नजर रखे हुए है। मार्च 2020 के पहले पखवाड़े में तरल ईंधनों की कुल मांग में 10 से 11 प्रतिशत की कमी आई है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 के दौरान देश में 195 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई थी। यदि दोनों पखवाड़ों में उपभोग बराबर मान लिया जाए तो मार्च 2019 के पहले पखवाड़े में करीब 100 लाख टन ईंधन की खपत रही होगी। यात्राओं को लेकर प्रतिबंध और परामर्श के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों में मंदी की वजह से मांग में यह कमी आई है। इस दौरान डीजल की बिक्री में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई है और जेट ईंधन की बिक्री में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पेट्रोल की बिक्री में दो फीसदी से अधिक की गिरावट देखी गई है।

आईओसी ने कहा कि विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बिक्री में 10 फीसदी की गिरावट आई है। बंकर ईंधन की बिक्री में भी लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। इस बीच क्रिसिल ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी ने मांग को और कमजोर कर दिया है। *भाषा*

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Mar 19	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,602.5	-9.2	1,867.0	-2.5
Copper	4,860.5	-21.1	5,480.9	-14.6
Nickel	11,420.0	-18.6	11,735.3	-19.1
Lead	1,616.0	-14.8	1,800.3	-19.1
Tin	14,075.0	-18.6	14,469.1	-20.0
Zinc	1,820.0	-21.7	1,880.3	-27.8
Gold ($/ounce)	1,473.5*	-0.4	1,673.0	0.9
Silver ($/ounce)	12.0*	-29.5	14.6	-24.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	24.1*	-64.4	27.2	-59.3
Natural Gas ($/mmBtu)	1.6*	-28.4	1.7	-26.1
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	181.0	-3.9	267.6	-11.6
Maize	181.5*	-0.6	210.8	-28.7
Sugar	334.4*	-6.7	459.3	-5.7
Palm oil	562.5	-21.3	943.5	-16.2
Rubber	1,329.7*	-16.2	1,700.3	-7.8
Coffee Robusta	1,201.0*	-10.3	1,793.6	-4.2
Cotton	1,224.2	-17.8	1,373.6	-13.4

* As on Mar 19, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 75.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	89.9	39835
Oil and Oilseeds	385.9	85903
Spices	0.0	8
Metal(Mar 18)		
Metal- non ferrous	7246.6	35786
Metal- precious	21384.8	364
Oil and gas(Mar 18)		
Gas	2524.8	25186
Oil	8996.3	2606

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	103.6	105156
Grains	158.5	68830
Oil and Oilseeds	664.3	339245
Others	107.8	51385
Pulses	115.3	45980
Spices	49.4	17990

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Mentha Oil (Mar 31)	1186.7	1.9
Crude Palm Oil (Mar 31)	641.4	1.9
Losers (* % Change)		
Crude Oil (Mar 19)	1619.0	-22.7
Natural Gas (Mar 26)	119.1	-9.1
Silver Micro (Apr 30)	35124.0	-7.7
Copper (Mar 31)	381.8	-6.5
Zinc Mini (Mar 31)	140.2	-4.7
Silver (May 05)	33907.0	-4.4
Silver Mini (Apr 30)	33931.0	-4.3
Zinc (May 29)	144.1	-4.3
Nickel (Mar 31)	857.2	-3.7
Cotton (Mar 31)	17510.0	-1.8

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Soyabean Indore (Mar 20)	3560.0	3.7
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5500.0	1.5
Mustard Seed Rape Oil (Apr 20)	3938.0	1.2
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Mar 20)	772.0	1.0
CottonSeed Oil-Akola (Mar 20)	1781.0	0.3
Losers (* % Change)		
Maize IndusNizamabad (Apr 20)	1343.0	-3.3
Chana-Bikaner (Mar 20)	4009.0	-1.0
Jeera Unjha (Mar 20)	13385.0	-0.9
Barley Jaipur (Apr 20)	1600.5	-0.8
GuarGum 5T-Jodhpur (Mar 20)	5144.0	-0.5
Guar Seed 10 (Mar 20)	3442.0	-0.3
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	982.0	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Copper Mum (Mar 31)	381.8	3.8
Silver Micro-Ahemd (Apr 30)	35124.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Apr 15)	2266.7	-12.4
Menthol Oil Chandaus (Mar 31)	1186.7	-8.8
Lead Mum (May 29)	132.8	-6.5
Lead Min Mumbai (Mar 31)	135.1	-4.9
Cotton-Rajkot (Mar 31)	17510.0	-3.5
Zinc Mini Mumbai (Mar 31)	140.2	-3.4
Gold Petal-Mumbai (Mar 31)	3916.0	-3.2
Silver Ahm (May 05)	33907.0	-3.1
Nickel Mumbai (Mar 31)	857.2	-2.3
Gold Ahm (Apr 03)	39723.0	-1.7

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Maize-Sangli (Mar 20)	1581.0	3.6
Bajra-Delhi (Mar 20)	1631.0	1.3
Paddy-Basmati-Karnal (Mar 20)	3001.0	0.9
29 mm Cotton-Rajkot (Mar 20)	18330.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1600.5	-5.9
Coriander-Kota (Apr 20)	5650.0	-4.4
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Mar 20)	5144.0	-3.8
Soy Bean Indore (Mar 20)	3560.0	-2.7
Jeera Unjha (Mar 20)	13385.0	-2.0
Crude Palm Oil Kandl (Mar 31)	625.7	-1.8
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5500.0	-1.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	107......................(107)
Aluminium ingots /kg	140......................(140)
Brass sheet cutting /kg	283......................(300)
Brass utensil scraps/kg	265......................(280)
Copper heavy scrap /kg	380......................(390)
Copper utensil scraps/kg	364......................(370)
Copper wire bar /kg	411......................(423)
Lead ingots /kg	135......................(140)
Nickel Cathodes /kg	880......................(890)
Tin slabs /kg	1085....................(1125)
Zinc slabs /kg	141......................(148)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10348.................(10348)
DCH - 32 /Qtl	10882.................(11023)
Jaydhar /Qtl	9251...................(9392)
Shankar- 6 /Qtl	10686.................(10826)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	818......................(820)
Castor Comm /10kg	808......................(810)
Groundnut oil /10kg	1280...................(1280)
Linseed oil /10kg	880 ....(-)
Karanji /10kg	790 ....(-)
Palm oil /10kg	724......................(723)
Sunflower exp ref /10kg	810......................(810)
Sunflower oil exp /10kg	725......................(725)
Soyabean ref / 10kg	760......................(760)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3336-3552 ....(3316-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	22.8..................(20.37)
Brent Crude (UK)	24.57 ....(24.56)
Brent Crude (WTI)	20.37...............(20.37)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.66 ....(1.6)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	176.65 ....(144.26)
Naptha spot /Rs/MT	45170.................(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.................(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.................(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40334.................(40375)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40496.................(40537)
Silver.999/ kg	35220.................(35515)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18322.75	18199.60
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.20	137.60
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1617.50	1610.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1629.65	1633.95
Barley Jaipur (N)	1 Q	1700.00	1700.00
Basmati-Amritsar (I)*	100 KG	3258.00	3279.00
Cardamom-Vand. (I)*	1 K	2683.00	2667.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	3853.35	3855.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	3775.00	3812.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	3981.20	4020.30
Chana Delhi (N)	1 Q	4195.85	4239.30
Chana-Akola (N)	X	4012.50	3962.50
Coriander-Gondal (N)	X	5708.00	5714.00
Coriander-Jaipur (N)	X	5700.00	5700.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	5925.50	5912.05
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1806.00	1816.65
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1881.45	1885.35
Cotton-Kadi (N)	1 B	18286.00	18190.40
CPO-Kandla (M)	10 K	625.00	636.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	624.45	637.20
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	625.00	630.00
Gold Ahm (M)	10 G	40649.00	40395.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32650.00	32446.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4055.00	4045.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	5300.00	5344.45
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3335.00	3421.65
Guarseed-Jodhpur (I)*	1 Q	3375.00	3325.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1076.95	1080.95
Isabgulseed-Unjha (I)*	1 K	103.80	104.70
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14100.00	14200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	13742.30	13652.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	778.85	782.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	982.20	970.90
Kapas-Rajkot (N)	X	975.70	968.85
Lead Mum (M)	1 K	143.50	142.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1640.00	1640.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	1716.65	1700.00
Maize-Erode (N)	X	1492.50	1500.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	1716.65	1700.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	1665.00	1660.00
Maize-Sangli (N)	X	1530.45	1525.50
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4500.00	4625.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7775.00	7781.25
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4037.90	4012.15
Nickel Mumbai (M)	1 K	888.10	877.40
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3000.00	2975.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)*	1 Q	2983.00	3027.00
Paddy-Basmati-Pusa (N)	X	2773.75	2850.00
Pepper-Ernakulam (I)*	1 K	320.00	322.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	32150.00	32563.65
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	797.50	797.50
Rape mustards-Patan (I)*	20 K	723.00	738.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1923.05	1930.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5303.20	5265.65
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	710.00	707.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	770.80	775.65
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	775.05	774.95
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	781.00	782.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	12900.00	12750.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)*	1 Q	12888.00	12800.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	35889.00	34977.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	3624.00	3658.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3484.50	3474.75
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3673.90	3686.50
Soy Bean-Akola (N)	X	3500.00	3465.00
Soymeal Indore (N)	1 T	29500.00	29800.00
Soyoil-Indore (I)*	10 K	764.80	769.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3170.00	3170.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3247.60	3257.15
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3203.35	3197.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3361.90	3371.45
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3192.05	3192.50
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3103.35	3100.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5571.45	5571.45
Wheat Delhi (N)	1 Q	2153.35	2151.80
Wheat Kota (N)	1 Q	1978.75	2011.90
Wheat New Indore (N)	1 Q	1800.00	1850.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	1980.00	2005.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	1770.00	1760.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5675.00	5650.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5075.00	5050.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	150.50	145.15

* as on Mar 18, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Mar 31	17460, 17530, 17410, 17510	4813	712	22105
Apr 30	17730, 17780, 17660, 17730	2874	440	14945
May 29	18010, 18030, 17910, 18010	948	116	1939
Jun 30	18120, 18120, 18120, 18120	04	1	179
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Mar 20	1740, 1796, 1740, 1781	1120	39	11070
Apr 20	1750, 1785, 1712, 1762	39340	2830	69090
May 20	1760, 1797, 1725, 1778	6010	535	18340
Jun 19	1780, 1825, 1768, 1803	620	59	3820
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	974, 983, 973, 981	88	21	668
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	972.5, 985, 970, 982	1066	563	2706
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1604, 1604, 1585.5, 1600.5	190	11	2450
May 20	1590, 1590, 1585, 1585	40	4	3480
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3422, 3450, 3382, 3442	1545	54	3090
Apr 20	3382, 3456, 3302, 3390	37560	4193	49450
May 20	3360, 3468, 3324, 3416	7490	816	9650
Maize IndusNizamabad NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1348, 1348, 1334, 1343	170	12	240
May 20	1355, 1355, 1341, 1341	70	6	460
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3652, 3702, 3652, 3702	10	2	170
Apr 20	3702, 3736, 3660, 3726	3105	355	18445
May 20	3646, 3700, 3638, 3700	1190	143	8780
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Mar 31	614, 652.9, 614, 641.4	25020	1800	27800
Apr 30	610, 638.8, 608.3, 630.3	26720	1765	37060
May 29	612.5, 635, 609, 628.1	5760	457	20730
Mentha Oil MCX(1 K)				
Mar 31	1199, 1210, 1160.5, 1186.7	118.08	258	129.6
Apr 30	1088.6, 1115, 1082, 1098.3	74.52	135	164.16
May 29	1070, 1087, 1060, 1066.9	8.64	23	9
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Apr 20	3866, 3949, 3858, 3938	8870	727	14780
May 20	3855, 3924, 3840, 3911	6610	450	14630
Jun 19	3855, 3920, 3855, 3915	390	33	2490
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Mar 20	761, 772, 761, 772	2090	126	16560
Apr 20	714.6, 745.6, 714, 743.4	43490	4752	44060
May 20	701.2, 728, 699.4, 725.6	12610	1374	10595
Jun 19	696.8, 708.4, 696.8, 708.4	50	10	95
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Mar 20	3574, 3574, 3560, 3560	15	3	35
Apr 20	3380, 3480, 3330, 3462	29790	3743	118115
May 20	3356, 3468, 3326, 3454	14205	1840	66600
Jun 19	3356, 3480, 3350, 3464	3085	374	23700
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	5130, 5315, 5122, 5144	375	29	315
Apr 20	5211, 5290, 5061, 5185	16140	2328	42490
May 20	5206, 5340, 5096, 5243	4240	620	8545
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4069, 4069, 3884, 4009	500	17	-
Apr 20	3904, 3935, 3888, 3912	17200	1217	24430
May 20	3922, 3956, 3897, 3911	9040	573	15910
Jun 19	3989, 3990, 3927, 3949	2630	194	5620
Jul 20	3990, 3990, 3990, 3990	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Apr 15	2300, 2300, 2233.3, 2266.7	0.2	2	5.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	5569, 5690, 5502, 5650	2260	206	5740
May 20	5603, 5630, 5450, 5551	1230	109	2920
Jun 19	5607, 5607, 5607, 5607	20	2	80
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13350, 13650, 13320, 13385	105	11	117
Apr 20	13310, 13500, 13125, 13410	1530	395	2046
May 20	13335, 13555, 13270, 13495	288	82	507
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5500, 5500, 5500, 5500	165	2	180
Apr 20	5500, 5570, 5478, 5524	535	91	5610
May 20	5492, 5588, 5492, 5570	60	12	770
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	131, 134.25, 131, 132.1	3	3	5
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Mar 31	135.35, 135.75, 127.7, 133.5	15567	10836	3692
Apr 30	135, 135.3, 128.2, 133.05	2262	1649	2527
Copper MCX(1 K)				
Mar 31	366.5, 374, 335.95, 360.6	34847.5	12151	6485
Apr 30	368.25, 375.5, 337.55, 363.2	4822.5	1551	1525
Lead MCX(1 K)				
May 29	130.05, 130.05, 128.1, 129.1	2	2	8
Lead Mini MCX(1 K)				
Mar 31	134.2, 134.2, 118.85, 128.45	23162	17800	2865
Apr 30	132.9, 133.05, 117.3, 127.55	3088	2259	1348
Nickel MCX(1 K)				
Mar 31	840.8, 899.5, 805.8, 839.4	23784	14278	1587
Apr 30	822.4, 861.9, 800.1, 832.8	1684.5	990	741
Zinc MCX(1 K)				
May 29	138.35, 142, 131.95, 139.45	81	51	72
Zinc Mini MCX(1 K)				
Mar 31	138.8, 138.8, 123.6, 136.5	46340	32154	8695
Apr 30	141.6, 141.6, 125.8, 137.9	6239	4432	6049
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	39307, 40099, 39052, 39688	7.7	6229	6.63
Jun 05	39500, 40189, 39230, 39828	1.21	1052	12.88
Aug 05	39576, 40275, 39576, 40117	0.05	34	0.37
Gold Guinea MCX(8 G)				
Mar 31	32711, 33280, 32550, 33079	0.01	1257	0.01
Apr 30	32600, 32947, 32302, 32691	0	358	0.01
Gold Mini MCX(10 G)				
Apr 03	39700, 40170, 39121, 39756	2.44	21321	0.52
May 05	39516, 40147, 39222, 39778	0.15	1278	0.37
Jun 05	39309, 40040, 39289, 39781	0.01	62	0.04
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Mar 31	3919, 3947, 3850, 3905	0.01	3830	0.01
Apr 30	3950, 3972, 3900, 3943	0	1523	0.01
May 29	3932, 3991, 3925, 3983	0	39	0
Silver MCX(1 K)				
May 05	34572, 34757, 33711, 34463	403.35	10744	242.34
Jul 03	34476, 35012, 34077, 34783	16.98	488	10.74
Silver Micro MCX(1 K)				
Apr 30	34800, 35779, 34565, 35469	52.35	40547	26.24
Jun 30	35222, 36133, 34701, 35838	3.04	2344	4.84
Aug 31	35903, 36869, 35200, 36214	0.01	6	0.04
Silver Mini MCX(1 K)				
Apr 30	34200, 34807, 33767, 34504	176.83	30195	52.35
Jun 30	35652, 36050, 34904, 35718	1.75	326	3.76
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Mar 26	122.3, 127, 121.3, 125.4	70904mb	40854	20661mb
Apr 27	127.3, 132.4, 126.3, 130.6	4676mb	2950	3378mb
May 26	132.2, 137.6, 132.1, 136.2	226mb	170	519mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Mar 19	1682, 1790, 1612, 1710	20238bl	128292	812bl
Apr 20	1807, 1902, 1733, 1827	6065bl	39073	1913bl
May 18	1900, 2060, 1881, 1987	62bl	443	45bl
Jun 19	2180, 2180, 2134, 2150	0bl	3	1bl
सायं सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Mar 31	17960, 18080, 17530, 17650	5523	912	23776
Apr 30	18230, 18310, 17780, 17910	3618	561	14583
May 29	18440, 18440, 18030, 18180	557	97	1361
Jun 30	18560, 18590, 18340, 18530	47	8	179
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	983, 985, 976, 979.5	472	96	664
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Mar 31	636.9, 643.1, 623, 629.4	30960	2212	29160
Apr 30	625.7, 631.8, 610.7, 615.5	27570	1875	41020
May 29	629.7, 635.8, 613, 615.1	9840	735	20320
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	137.95, 137.95, 134.35, 135.8	3	3	4
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Mar 31	137.4, 137.4, 134.4, 135.7	11231	8603	3317
Apr 30	137.3, 137.3, 135.05, 135.65	1099	915	2144
Copper MCX(1 K)				
Mar 31	409, 409.4, 379.7, 381.75	60010	20688	6995
Apr 30	411.6, 411.6, 381.7, 383.55	4607.5	1675	2037.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Mar 31	137.8, 138.25, 133, 135.05	32533	22733	2943
Apr 30	137.45, 137.5, 132.4, 133.9	2410	1871	1470
Nickel MCX(1 K)				
Mar 31	905.9, 905.9, 853, 857.2	35149.5	21749	1290
Apr 30	889.8, 893.3, 849.6, 851.1	771	496	603
Zinc MCX(1 K)				
May 29	149.1, 149.1, 142.85, 144.1	20	17	37
Zinc Mini MCX(1 K)				
Mar 31	147.6, 148.05, 138.8, 140.2	59976	41208	9345
Apr 30	149.15, 149.7, 141.1, 142.4	5787	4147	5542
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40127, 40447, 39318, 39723	22.19	18527	6.65
Jun 05	40434, 40645, 39480, 39903	3.2	2545	12.76
Aug 05	40046, 40220, 39827, 40058	0.04	22	0.34
Gold Guinea MCX(8 G)				
Mar 31	33261, 33299, 32450, 32956	0.05	4113	0.01
Apr 30	33100, 33194, 32402, 32652	0.01	853	0.01
May 29	32500, 32600, 32010, 32405	0	4	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Apr 03	40239, 40480, 39368, 39764	7.25	63728	0.45
May 05	40304, 40554, 39500, 39840	0.46	3274	0.38
Jun 05	40493, 40638, 39500, 39825	0.04	386	0.04
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Mar 31	4000, 4005, 3866, 3916	0.04	10598	0.01
Apr 30	4014, 4040, 3930, 3954	0.01	3605	0.01
May 29	4037, 4057, 3956, 3983	0	80	0
Silver MCX(1 K)				
May 05	35700, 36486, 33580, 33907	1453.47	37933	251.88
Jul 03	36378, 36456, 34076, 34422	81.69	2397	7.08
Silver Micro MCX(1 K)				
Apr 30	37980, 40287, 34663, 35124	189.39	139873	24.43
Jun 30	38955, 40500, 35200, 35553	10.78	7896	4.83
Aug 31	39101, 39982, 36417, 37398	0.03	24	0.04
Silver Mini MCX(1 K)				
Apr 30	35989, 36256, 33622, 33931	579.34	97605	50.94
Jun 30	36764, 38115, 35151, 35404	12.41	2166	3.7
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Mar 26	128.3, 128.3, 118.5, 119.1	196074mb	105639	21054mb
Apr 27	133, 133.2, 124.1, 124.5	7484mb	5037	3630mb
May 26	137.5, 138.2, 129.3, 129.8	446mb	297	503mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Mar 19	2016, 2036, 1583, 1619	41631bl	251597	819bl
Apr 20	2101, 2139, 1717, 1739	6768bl	40439	1745bl
May 18	2184, 2262, 1875, 1910	66bl	482	42bl
Jun 19	2231, 2380, 2204, 2270	1bl	10	1bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श की बढ़ी मांग

देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सक ऑनलाइन सेवाओं को वरीयता दे रहे हैं, वहीं यात्रा प्रतिबंधों के कारण चिकित्सा पर्यटन लगभग थम सा गया है, जिसका अस्पतालों की आय पर पड़ेगा असर

सोहिनी दास

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर दूरी बनाने के बढ़ते चलन से अस्पताल तथा क्लीनिक प्रभावित होने लगे हैं। इस महामारी से बचने के लिए अधिकांश लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं और वर्चुअल सलाह को वरीयता दे रहे हैं। साथ ही, वीजा प्रतिबंधों के चलते चिकित्सा पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है।

ऑनलाइन सलाह के बढ़ते चलन के बीच डिजिटल हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने फिजिशियन से सलाह लेने के मामलों में 3-4 गुना तेजी दर्ज की है।

प्रैक्टो के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्लॉफॉर्म पर एक सामान्य चिकित्सक आमतौर पर रोजाना 24-30 मरीजों को देखता था जबकि अब यह संख्या 3-4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा, 'चिकित्सकों को सुबह 2-3 बजे, रात्रि 10-11 बजे चिकित्सकीय सलाह के लिए आवेदन आ रहे हैं। क्भारतीय काफी चिंतित हैं और मामूली लक्षण होने पर भी चिकित्सकीय परामर्श ले रहे हैं। साथ ही, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हालिया जोखिम के चलते अस्पताल नहीं जाना चाहते और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।'

प्रैक्टो पर पिछले सप्ताह आने वाले सभी आवेदनों में से 53 प्रतिशत कोरोनावायरस से संबंधित थीं। प्रवक्ता ने बताया, 'हमने पिछले चार सप्ताह में अपने चिकित्सकों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ा दी है जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हम मरीजों को दूरस्थ सलाह देने के उद्देश्य से अस्पतालों तथा चिकित्सकों तक पहुंच बना रहे हैं। इससे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना पड़ता और मेडिकल स्चाफ को भी संभावित मरीज से दूर रखता है।'

प्रैक्टो ने उपयोगकर्ताओं से रिपोर्ट, तस्वीरें तथा वीडियो कॉल का उपयोग करने के लिए कहा है। ये सेवाएं सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध हैं। कंपनी के मुख्य स्वास्थ्य रणनीति अधिकारी एलेक्जेंडर कुरुविला बताते हैं, 'रोजाना नवए मामले सामने आने से कोरोनावायरस ने घबराहट पैदा कर दी है। सामान्य सर्दी-जुकाम के लक्षणों से मेल खाते कोरोनावायरस के लक्षण से दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया है। लोग भीड़भाड़ वाले अस्पतालों में जाने के बजाय ऑनलाइन सलाह लेना मुनासिब समझ रहे हैं।'

- कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण अस्पताल और क्लिनिक जाने से बच रहे लोग
- वीजा और आगमन पर प्रतिबंधों के कारण इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिक कम हुए
- डिजिटल हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो पर सामान्य फिजिशियन से परामर्श लेने वाले चार गुना बढ़े

वर्चुअल तथा टेलीफोन के जरिये सलाह लेने वाले मरीजों की संख्या में आ रही है तेजी

ई-फार्मेसी तथा हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म 1एमजी पर सर्दी-जुकाम के लक्षणों के साथ सलाह लेने वाले लोगों की संख्या में मार्च के बाद से 300 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता के चलते देशभर से परामर्श संबंधी कॉल आ रही हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के एक अन्य प्लेटफॉर्म डॉकऑनलाइन के अनुसार भी देश के टेलीमेडिसिन क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के संस्थापक तथा बोर्ड सदस्य मारकस मोदिंग ने कहा, 'डॉकऑनलाइन पर फरवरी के मुकाबले मार्च में संख्या दोगुनी हो गई।'

एक तरफ वर्चुअल तथा टेलीफोनिक सलाह लेने की संख्या में तेजी आ रही है वहीं अस्पतालों में आने वाले लोगों की संख्या घट रही है, विशेषकर विदेशी मरीजों की। वीजा प्रतिबंधों के चलते कम विदेशी मरीज भारत आ रहे हैं। उद्योग का कहना है कि भारत की यात्रा करने वाले मरीजों में सर्जरी तथा कंसल्टेशन लेने वालों की संख्या अधिक हैं लेकिन उन्होंने अब अपनी यात्राएं स्थगित कर दी हैं।

मणिपाल हॉस्पिटल्स के मुख्य कार्याधिकारी दिलीप जोस बताते हैं कि अभी भारत में रह रहे मरीज ही अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पताल के 6-7 फीसदी मरीज विदेशी नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा, 'अप्रैल में मरीजों की संख्या में वास्तविक गिरावट देखने को मिलेगी, जब कोई बी अस्पतान नहीं जाना चाहेगा और स्थिति बेहतर होने का इंतजार करेगा।'

जोस ने आगे कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू रोगी के लिए प्रति व्यक्ति औसत राजस्व में लगभग 7-8 प्रतिशत का अंतर है।

हालांकि अस्पताल मार्च तिमाही के आंकड़े साझा नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि विदेशी नागरिकों की कमी से काफी नुकसान होगा।

कोलकाता स्थित मेडिका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन आलोक रॉय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'प्रत्येक महीने हमारे पास करीब 1000 नए रोगी (मेडिकल टूरिस्ट पर) आते थे जिसमें रिव्यू तथा स्वास्थ्य जांच के लिए आने वाले मरीज भी शामिल हैं। फिलहाल हम एक महीने में करीब 4,000 देख रहे हैं।' ये मरीज मुख्यत: बांग्लादेश, भूटान और दूसरे देशों से आते हैं। मेडिका अस्पतालों की कुल कमाई में मेडिकल टूरिज्म का हिस्सा करीब 8 प्रतिशत है।

हालांकि मेडिका की कमाई में भी तेज गिरावट आई है। रॉय का कहना है कि रोजाना 100 मरीजों से संख्या घटकर करीब 6 मरीज पर आ गई है। उन्हें महसूस होता है कि आने वाले दिनों में यह संख्या भी लगभग खत्म हो जाएगी।

दिनोंदिन गहराता संकट

- दुनिया भर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,19,000 और मरने वालों की तादाद 8,900 से अधिक हुई
- इटली ने कोरोना से प्रभावित अपने एक उत्तरी शहर में सेना को मृतकों को हटाने को कहा है क्योंकि वहां अंतिम संस्कार की सेवाएं कम पड़ रही हैं। वहां की सरकार देश भर में बंदी के आपात उपायों का विस्तार करने की तैयारी कर रही है
- फ्रांस में 15 दिन के बंद को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहां मृतकों की संख्या बढ़कर 264 हो गई।
- जर्मनी में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 10,999 हुए। मृतक संख्या 20 हुई।
- जर्मनी ने महामारी से जंग में मदद के लिए लाखों आरक्षित सैन्यकर्मी बुलाए
- ब्रिटेन लंदन को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वहां भूमिगत ट्रेन स्टेशन पहले ही किए जा चुके हैं बंद
- अमेरिकी सीनेट ने कोरोनावायरस सहायता पैकेज को मंजूरी दी। अन्य पैकेज पर हो रहा काम।
- अमेरिका में बेरोजगारी के दावों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के आसार

- वैश्विक बिकवाली से एशिया के कई बाजारों में भारी गिरावट
- डॉलर में मजबूती, प्रोत्साहनों के बाद बॉन्ड में बढ़ोतरी
- लोगों की चिंता से प्रभावित वैश्विक वित्तीय बाजारों को मजबूत करने के लिए आगे आए वैश्विक नेता
- दक्षिण कोरिया ने छोटे कारोबारियों के लिए 39 अरब डॉलर के आपत कोष की घोषणा की
- यूरोपीय संग के ब्रेक्जिट के मुख्य वार्ताकार को कोरोनावायरस
- तेल युद्ध और वायरस के कारण सऊदी अरब ने खर्च में 13.3 अरब डॉलर की कटौती की
- मलेशिया ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आरक्षित कोष 6.8 अरब डॉलर घटाया

रविवार को देश भर में लगेगा `जनता कर्फ्यू'

पृष्ठ 1 का शेष

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर और सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों से जनता कर्फ्यू के बारे में लोगों को संदेश देने और जागरूक बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह कर्फ्यू कोरोनावायरस जैसी महामारी के खिलाफ भारत की मुस्तैदी परखने की कसौटी है।

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के कारण पिछले कुछ समय से लोग बाजारों से सामान खरीदने और भंडारण करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र करते हुए कहा कि देश में किसी तरह की सामग्री की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसीलिए घबराहट में ढेर सारा सामान खरीदकर घर में इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी होड़ में न जुटें और सामान्य तौर पर जैसी खरीदारी की जाती है, वैसी ही खरीदारी करते रहें। मोदी ने कोरोनावायरस के संकट को अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इसकी आर्थिक चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यबल गठित किया गया है। कार्यबल स्थिति पर नजर रखेगा, संबंधित पक्षों से बात करेगा और अनुकूल कदम उठाएगा।

उन्होंने छंटनी की आशंका देखते हुए कारोबारी जगत और उच्च आय वर्ग से अपने लिए काम करने वालों के आर्थिक हितों का ध्यान रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन कर्मचारियों का भी परिवार होता है और उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के समय में एक ही मंत्र काम करता है, 'हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ।' जब विज्ञान इस बीमारी की दवा नहीं ढूंढ पाया है और इसका कोई टीका भी नहीं है तो अपनी और परिवार की सेहत की देखभाल खुद करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें अन्यथा घर से ही काम करें। उन्होंने 60-65 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कुछ समय के लिए घरों में ही रहने की सलाह दी।

मुंबई में पसरने लगा सन्नाटा

सुशील मिश्र

कोरोनावायरस को लेकर देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। अभी तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। कभी न बंद होने वाले डब्बा वालों ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। एसी लोकल सेवा भी शुक्रवार से बंद हो जाएगी। लगभग सभी मंदिर, पर्यटन स्थल, होटल, बार, पब इत्यादि पहले ही बंद हो चुके हैं। आधी दुकानें बंद कर दी गई हैं। लोगों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। ऐसा न करने पर सार्वजनिक परिवहन सेवा पूरी तरह बंद करने की सरकार की तरफ से चेतावनी भी दी गई है।

सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें। सरकार की अपील को मानते हुए मुंबई के मशहूर डब्बा वालों ने 31 मार्च तक सेवा बंद कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील है कि वे बस और ट्रेनों की यात्रा कम करें। ठाकरे ने कहा कि शिवाजी का महाराष्ट्र, लड़ेगा और जीतेगा। उन्होंने अपील है कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अलावा कुछ और ना करें।

भारत-ईरान कारोबार पर गंभीर असर

नम्रता आचार्य और अभिषेक रक्षित

कोरोनावायरस के भय से भारत तथा ईरान के बीच कारोबार करीब करीब ठप होने के कगार पर है। यूको बैंक तथा आईडीबीआई बैंक इस द्विपक्षीय कारोबार के लिए के लिए भुगतान सुविधा उपलब्ध कराते हैं और इस स्थिति में इन दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा। यूको बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ईरान के साथ कारोबार के उद्देश्य से जमा धन में तेजी से कमी आई है और बैंक धनराशि उपलब्ध होने तक समर्थन का विस्तार करता रहेगा।

यह निर्यातकों के लिए दोहरी मार होगी क्योंकि वे पहले से ही पिछले महीने से कंटेनरों की भारी कमी के चलते ईरान से कारोबार में जूझ रहे हैं। चीन से इन कंटेनरों की सबसे अधिक आपूर्ति की जाती है और दुनियाभर की कंटेनर आपूर्ति में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।

अगर आयात तथा निर्यात, दोनों पर रोक लगती है तो बैंकों के लिए भुगतान तंत्र अनावश्यक हो जाएगा। दोनों बैंकों ने ईरान से होने वाले कारोबार के लिए जमा राशि का खुलासा नहीं किया। हालांकि इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2018-19 की अंतिम तिमाही में यूको बैंक के घाटे में 27 प्रतिशत की कमी कर सका क्योंकि बैंक को भारतीय तेल रिफाइनरियों से 13,000-14,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फ्लोटिंग फंड मिला था। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत वहां डॉलर के साथ होने वाले कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए, रुपया-रियाल आधारित कारोबारी तंत्र लाया गया है। इसके तहत भारत से तेल रिफाइनरियां ईरान से आयात के लिए नामित बैंकों में रुपये जमा करती हैं और इस फंड का उपयोग भारत से ईरान के निर्यातकों के लिए बकाया राशि देने में किया जाता है।

ईरान को निर्यात 2018-19 में 3.5 अरब डॉलर था जो चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के बीच 2.8 अरब डॉलर रहा

हालांकि पिछले करीब छह महीने से भारत से ईरान से तेल आयात रोक दिया है। इसलिए तेल कंपनियों ने भी इस बैंकों में रुपया जमा कराना बंद कर रखा है। हालांकि इस अनुपात में निर्यात में कमी नहीं आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ईरान से भारत का तेल आयात वर्ष 2018-19 में करीब 13 अरब डॉलर का था जो चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों (अप्रैल 2019-जनवरी 2020) में गिरकर 1.35 अरब डॉलर पर आ गया। इस परिप्रेक्ष्य में, निर्यात में गिरावट कम रही। भारत से ईरान को निर्यात 2018-19 में 3.5 अरब डॉलर था जो चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के बीच 2.8 अरब डॉलर रहा। चावल, चाय, चीनी और दवा उत्पाद भारत से ईरान को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद हैं। इसमें चावल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक विनोद कौल का कहना है कि ईरान के साथ सेगमेंट कारोबार कंटेनरों की भारी कमी के साथ बंद हो गया है। पिछले साल भारत ने ईरान को लगभग 14 लाख टन चावल का निर्यात किया था। कौल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में यह 10 लाख टन से ज्यादा नहीं रहेगा।

ईरान को चाय निर्यात करने वाले कारोबारियों का यह भी कहना है कि कंटेनरों की अनुपलब्धता के कारण शिपमेंट एक जगह इकट्ठा हो गया है; इसके अलावा, शिपिंग कंपनियां वहां खेप भेजने के लिए भी तैयार नहीं हो रही हैं। असम के एक चाय बागान के मालिक ने कहा, 'अग्रिम ऑर्डर देने के लिए बहुत से ईरानी यहां आने में सक्षम नहीं हैं और न ही हम सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए वहां जा सकते हैं। इस साल यह बाजार गंभीर रूप से प्रभावित होगा।' आमतौर पर चाय कंपनियों के लिए फरवरी से अप्रैल के बीच का सत्र प्रमुख होता है क्योंकि इस दौरान अग्रिम सौदों पर हस्ताक्षर होते हैं।

इन अनुबंधों में कीमतें तथा कुल निर्यात मात्रा तय की जाती है और इसके हिसाब से कंपनियां पैदावार करती हैं।

जून से दिसंबर 2019 के बीच ईरान को निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भुगतान में काफी देरी का सामना करना पड़ा जिसकी कुल कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये थी। बार में सरकार के हस्तक्षेप से बकाया चुकाया गया।

घर से काम करने पर बढ़े ओटीटी शो के दर्शक

कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम का विकल्प दिया है, जिससे ओटीटी दर्शकों में 20 फीसदी इजाफा

सोहिनी दास

कोरोनावायरस के मामले बढ़ने के साथ ही कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है ऐसे में पिछले कुछ दिनों में ओवर दि टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की तादाद में तेजी देखी जा रही है। ज्यादातर ओटीटी मंच पर दर्शकों की तादाद में 20 फीसदी का इजाफा हुआ है खासतौर पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु जैसे महानगरों के दर्शकों में बढ़ोतरी हुई है।

दफ्तर में आने जाने पर रोजाना खर्च होने वाला समय बच रहा है ऐसे में लोग ऑनलाइन वीडियो सामग्री देखने के लिए ज्यादा वक्त दे पा रहे हैं। एक भारतीय ओटीटी मंच के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'सुबह का ज्यादातर वक्त दफ्तर आने-जाने और फिर फोन कॉल में खर्च हो जाता है। लेकिन अब टीवी पर भी सामग्री देखने की रफ्तार में तेजी दिख रही है।'

ज़ी5 की सामग्री भी खूब देखी जा रही है। इसके प्रवक्ता ने बताया, 'पिछले हफ्ते से लोग घर से काम कर रहे हैं इसी वजह से दर्शकों में बढ़ोतरी दिख रही है।' ज़ी5 की सामग्री देखने वाले भी ज्यादातर महानगरों के लोग हैं और दर्शक विभिन्न भाषाओं की सामग्री देख रहे हैं।

हंगामा डिजिटल मीडिया के संस्थापक और सीईओ नीरज रॉय कहते हैं, 'कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए ज्यादातर कंपिनयों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दे दी है या फिर कुछ कंपनियां ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। हमने 1 मार्च से 16 मार्च के बीच हंगाम प्ले पर स्ट्रीमिंग की तादाद में 20 फीसदी का इजाफा देख रहे हैं। इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी का अनुमान है क्योंकि लोग संक्रमण के डर से एक-दूसरे से दूरी बरत रहे हैं ऐसे में सामाजिक संवाद की कमी डिजिटल माध्यम के जरिये पूरी की जा रही है।'

रॉय ने कुछ और दिलचस्प रुझानों की तरफ इशारा किया। स्ट्रीमिंग की तादाद बढ़ने के अलावा हंगामा पर कुछ खास वक्त पर दर्शक मिलते हैं। उनका कहना है, 'सुबह में 8 बजे से 10.30 बजे के बीच दर्शकों की तादाद ज्यादा होती है और अब सुबह 11.30 बजे तक दर्शक ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं।'

वहीं शाम में भी पहले के 8 बजे के बजाय अब 6 बजे के बाद ही दर्शकों की तादाद बढ़ जाती है जो मध्यरात्रि तक जारी रहता है। रॉय कहते हैं, 'हमने वीडियो देखने वाले दर्शकों की संख्या में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भी तेजी देखी है जो आमतौर पर लंच का वक्त होता है।' अब तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु जैसे महानगरों में दर्शकों की तादाद में वृद्धि देखी जा रचही है जहां लोग छोटे शहरों की तुलना में दफ्तर जाने में ज्यादा वक्त खर्च करते हैं। हालांकि ओटीटी मंचों को उम्मीद है कि छोटे शहरों में भी ऐसा रुझान जल्द ही देखा जाने लगेगा क्योंकि अगले एक महीने तक संक्रमण की वजह से लोग एक-दूसरे से दूरी बनाकर रहेंगे। वायकॉम 18 के ओटीटी मंच वूट ने भी इस महीने के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन आधारित मंच वूट सेलेक्ट लॉन्च किया है। इसमें कुछ ओरिजिनल सीरीज वाली सामग्री भी दी जा रही है।

महानगरों में दर्शक सबसे ज्यादा बढ़े

वूट सेलेक्स नया मंच है और वायकॉम 18 के युवा, म्यूजिक और अंग्रेजी मनोरंजन प्रमुख फरजाद पालिया कहते हैं दर्शक सबस्क्रिप्शन आधारित सामग्री की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब अतिरिक्त समय भी है। पालिया ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हम 60 दिनों में जितने दर्शकों को जोड़ने की उम्मीद कर रहे थे उतना पहले 10 दिनों में ही हो चुका है।'

इस बीच टेलीविजन सीरीज और फिल्मों की शूटिंग रुक गई है। आमतौर पर चैनल किसी सीरियल के तीन से चार एपिसोड पहले से ही रखते हैं। लेकिन शूटिंग बंद होने की वजह से सीरियल से जुड़े नए टेलीविजन कंटेंट की रफ्तार धीमी होगी और प्रसारकों को पुराने एपिसोड का प्रसारण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश के एक अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बताया कि दर्शक सीरियलों के पुराने एपिसोड भी देख रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'ओटीटी के दर्शकों में 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि दर्शकों के पास सीमित विकल्प है।' कई ओटीटी मंचों को यह भी उम्मीद है कि जो दर्शक इस वक्त उनसे जुड़े हैं वे आगे भी ऑनलाइन वीडियो देखना जारी रखेंगे।

बढ़े विज्ञापनदाता?

फूड और ऑनलाइन डिलिवरी सेवाओं जैसी श्रेणियों में भी दबाव दिख रहा है। कोरोनावायरस की वजह से बड़े इवेंट मसलन इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन टाल दिया गया है। यह विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन खर्च के लिहाज से बड़ा मंच हुआ करता है। ऐसे में डिजिटल और ओटीटी मंचों पर विज्ञापन खर्च बढ़ने के आसार हैं।